RNI: UPHIN/2015/63899

मासिक, फरवरी 2019, ₹15/-

व्यवस्था दर्पण

बेबाक, निष्पक्ष, निर्भीक

देश द्रोह !

18

BSP

अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को

महाशिवरात्रि एवं होली की

हार्दिक शुभकामनाएं

आपका

अजीत बालियान

प्रत्याशी, 15 लोकसभा अलीगढ़

बसपा + सपा + रालोद महागठबंधन

व्यवस्था दर्पण

वर्ष–4, अंक–7, फरवरी 2019, मूल्य– 15 रूपये

RNI: UPHIN/2015/63899

संपादक

जियाउर्रहमान

उपसंपादक	:	आमिर साबरी (लखनऊ)
प्रबंध सम्पादक	:	किरनपाल सिंह
सलाहकार सम्पादक	:	दिनेश गुर्जर, डिंकल अग्रवाल, आर ए चौधरी
सहयोगी	:	आरती कपूर, सूरज बघेल, अरबाज खान
कानूनी सलाहकार	:	चौ. बलवीर सिंह एड. अनीस चौहान एड. प्रतीक चौधरी एड.

ब्यूरो प्रभारी

अलीगढ़	:	विवेक शर्मा, मधुरेश शर्मा
नई दिल्ली	:	अंकिता सिंह
राजस्थान	:	शिवम अग्रवाल
बिहार	:	नौशाद वारसी
इलाहाबाद/पूर्वी यूपी	:	शशांक मिश्रा
लखनऊ	:	आफक मंसूरी
गौरखपुर	:	राशिद अकेला
मेरठ	:	आकेश पांडेय, मिहिर सक्सैना
बुलन्दशहर	:	शुभम अग्रवाल
गौ. बुद्धनगर(नोएडा)	:	अमित शर्मा
सीतापुर	:	प्रफुल्ल रस्तोगी
बंदायू	:	योगेश यादव एड.
बरेली	:	इमरान रजा.
संभल	:	जाहिद नूर
हाथरस	:	मनोज कुमार वार्ष्णेय
बिजनौर	:	आसिफ रईस
आगरा	:	कुँवर नफीस अहमद

मुख्य कार्यालय

402, तृतीय तल, द ग्रेट शॉपिंग मॉल, विद्या नगर, रामघाट रोड, अलीगढ, उ.प्र.- 202001, 0571–3264777

लखनऊ कार्यालय

प्रथम तल, करीम प्लाजा, टैक्सी स्टैंड, अमीनाबाद लखनऊ- 26018

09454391714, 09719969790, 9410672481

Email: **editorvdarpan@gmail.com**
vyavasthadarpan@gmail.com
website: www.vyavasthadarpan.com
(News portal)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक जियाउर्रहमान द्वारा वर्ल्ड मीडिया सोल्यूशन, द ग्रेट शॉपिंग मॉल, रामघाट रोड अलीगढ़ से मुद्रित कराकर 402ए तृतीय तल, द ग्रेट शॉपिंग मॉल रामघाट रोड, अलीगढ़ (उ.प्र.) से प्रकाशित

समस्त वाद–विवाद का न्याय क्षेत्र अलीगढ़ उप्र होगा। पत्रिका में प्रकाशित लेख–समाचारों में सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं। इसका उत्तरदायित्व लेखक का होगा। सभी पद अवैतनिक हैं।

अंगूठा छाप और माफिया चला रहे हैं स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी... -5

गडकरी के बयान की गंभीरता को समझे नेता -8

'सोशल मीडिया ने विश्व को जोड़ा, एएमयू की बनाई जा रही गलत छवि' -16

2019 की बिसात पर राहुल की व्यूह रचना -27

तू इधर उधर की बात न कर -31

बाजारबाद के इस दौर में प्रेम भी तोहफों का मोहताज हो गया -33

सम्पादकीय

सैंकड़ों वर्षों की गुलामी से स्वतंत्रता की ओर लाने में यूं तो तमाम सारे महापुरूषों ने देश की आजादी के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया लेकिन महानायक के रूप में यदि किसी को जाना जाता है तो वह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचन्द गांधी। आजादी के आंदोलन में गांधी जी अपना एक अहम योगदान है। जिन अंग्रेजों को देखकर लोग अपने रास्ते बदल लिया करते थे वहीं लोग बाद में अंग्रेजों से मुकाबला करने लगे। इस जाग्रति का यदि श्रेय किसी को जाता है तो वह महात्मा गांधी को जाता है। जिन्होंने अहिसंक रूप से देश में बड़े बड़े आंदोलन चलाकर विभिन्न वर्गों और धर्मों में बंटे लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। दशकों चले संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिल गई लेकिन अगले ही वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या ने विश्व को झकझोर दिया। भारतीय कानून ने अपना काम किया और हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। आजादी के सात दशक बाद एक बार फिर नाथूराम गोडसे की विचारधारा देश में फन उठा रही है। महात्मा गांधी की 71 वी पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ में नाथूराम गोडसे की भक्तों ने न सिर्फ महात्मा गांधी के हत्यारे का गुणगान किया बल्कि उनके पुतले को गोली मारने का नाट्य कर विश्वभर में कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि पिछले लंबे समय से देश के नौजवानों और लोगों को गांधी के प्रति दुष्प्रचार कर उन्हें बदनाम करने की साजिश चलती आ रही है।

अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को जितना भारत में सम्मान दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा विश्व के विभिन्न देशों में उन्हें माना जाता है। गांधी के जन्म दिवस को पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है लेकिन अब भारत में गांधी और गांधी की विचारधारा के कातिलों के प्रति प्रेम और उनकी जयजयकार ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आजाद भारत में एक वर्ग और विचारधारा विशेष के लोग कभी हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते है तो कभी उनके पुतले को गोली मार रहे है। देशभर में इस कृत्य को लेकर अजीब खामोशी है जो हमारे अस्तित्व पर कई सवाल खड़े करती है। पहला यह है कि क्या सिर्फ सात दशक में ही देश और देश के लोग महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा को भूलने लगे है? क्या सिर्फ सात दशक में ही यह जरूरत आन पड़ी है कि गांधी के हत्यारे का गुणगान किया जाए। क्या देश में एक बार फिर विदेशी ताकतों के इशारे पर अराजक तत्वों को शरण देकर नफरत के बीज बोयें जा रहे है? धर्म और जाति के हावी होते इस दौर में क्या देश की राजनीति राष्ट्रपिता के कातिलों और कातिलों का गुणगान करने वाली विचारधारा को पाल पोस रही है?

सवाल बहुत है और जबाब एक भी नहीं। जिस गांधी ने राष्ट्र के लिए सब कुछ छोड़कर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को आजादी दिलायी आज उसी देश में देश के राजनेता उनकी विचारधारा और महत्व को संजाये रखने में विफल साबित हो रहे है। संविधान प्रत्येक नागरिक को महापुरूषों का सम्मान करने, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का कर्तव्य तो निर्धारित करता है लेकिन इस दौर में आकर नागरिक महापुरूषों को ही बांटने में तुले है। अभी तो यह शुरूआत है । यदि देश की सियासत और आमजन ने ठोस कदम वक्त रहते नहीं उठाये और गोडसे की विचारधारा का गुणगान करने वालों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की तो भविष्य में इसके बहुत घातक परिणाम होंगे। हमें और आपको को मिलकर तय कर ना होगा कि अब हम देश को गांधी की विचारधारा पर चलकर आगे बढ़ाना चाहते है या फिर उनके हत्यारें का समर्थन करकर विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहते है।

आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों की आशा के साथ ...

आपका

जियाउर्रहमान
editorvdarpan@gmail.com

बांटो और राज करो की राह पर 2019 के लोकसभा चुनाव

▸ निर्मल रानी

2014 के लोकसभा चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सबसे प्रमुख नारा देश के मतदाताओं के मध्य उछाला था वह था सबका साथ–सबका विकास। देश की जनता ने इस नारे पर विश्वास करते हुए तथा 2014 के चुनाव अभियान में दिखाए जाने वाले अनेक सुनहरे सपनों पर यकीन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सत्ता सौंपी थी। परंतु सत्ता में आते ही सबका साथ–सबका विकास का नारा न जाने कहां चला गया। आज तक देश विकास को ढूंढता फिर रहा है।

परंतु जिन बातों का जिक्र 2014 के चुनाव से पूर्व सुना भी नहीं जाता था वह सबकुछ देखा व सुना जा रहा है अर्थात् घर वापसी,लव जेहाद,गाय और गंगा,कुंभ स्नान,कांवड़ियों को अतिरिक्त सरकारी सुविधाएं व उनपर विमान से पुष्प वर्षा,बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष गीता महोत्सव का आयोजन,भाजपाई मीसा बंदियों को पेंशन, साधुओं को विशेष पेंशन,बूचडखनों पर पाबंदी,ईद और दीवाली में बिजली वितरण जैसे अनावश्यक व समाज को बांटने वाले अनेक मुद्दे,आरक्षण पर होती सियासत,तीन तलाक पर अनावश्यक बहस तथा अंततोगत्वा अपने आलोचकों तथा विपक्षी पार्टियों यहां तक कि कांग्रेस जैसे देश के सबसे जिम्मेदार व प्रतिष्ठित राजनैतिक संगठन को समाप्त करने जैसी बातें जरूर सुनाई दीं।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए यह सवाल पूछा था कि-क्या कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है या मुस्लिम महिलाओं या बहनों की भी है? यह कहकर मोदी ने भारतीय मुसलमानों को पुरुष व महिलाओं के मध्य विभाजित करने की चाल चली थी बल्कि हिंदू मतदाताओं को भी यह संदेश देने का प्रयास किया था कि कांग्रेस मुसलमानों का पक्षधर संगठन है।

ऐसा नहीं है कि देश को इन सब गैर जरूरी मुद्दों का सामना अनायास ही करना पड़ रहा है। बल्कि यह सब एक बड़ी व सोची–समझी साजिश के तहत किया जा रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों को यह सीख अंग्रेजों से ही प्राप्त हुई है। अंग्रेजों ने भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर बांटो और राज करो के फार्मूले को अपना कर ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। भारतीय जनता पार्टी भी देश में अपने राजनैतिक लाभ के अनुसार जात,धर्म,क्षेत्र,भाषा,क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार ण्राजनैतिक नफे–नुकसान के मद्देनजर राजनीति कर रही है। और हद तो यह कि अपने वोट बैंक की खातिर भाजपा सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्देशों व आदेशों को मानने से भी इंकार करती रही है। सबरीमाला मंदिर व जलीकुट्टु जैसे कई मामलों पर भाजपा का नजरिया यही दर्शाता है। देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुलाई 2018 में आजमगढ़ की एक जनसभा में दिया गया वह वक्तव्य याद होगा जब तीन तलाक विषय पर अपनी पीठ थपथपाने का अभियान चलाते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए यह सवाल पूछा था कि–क्या कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है या मुस्लिम महिलाओं या बहनों की भी है? यह कहकर

मोदी ने भारतीय मुसलमानों को पुरुष व महिलाओं के मध्य विभाजित करने की चाल चली थी बल्कि हिंदू मतदाताओं को भी यह संदेश देने का प्रयास किया था कि कांग्रेस मुसलमानों का पक्षधर संगठन है। बड़े आश्चर्य की बात है कि भाजपा को तीन तलाक के गलत तरीके का सामना करने वाली मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का कथित हनन होता तो दिखाई दिया परंतु उन्हें विभिन्न मंदिरों में प्रवेश न कर पाने वाली महिलाओं के अधिकारों की कोई फिक्र नहीं हुई। उन्हें हरिद्वार,वृंदावन,बनारस तथा अयोध्या में भटकने वाली लाखों बेसहारा,वृद्ध,मजबूर व अपने पतियों द्वारा त्यागी गई हिंदू महिलाओं की कोई चिंता नहीं। समाज को विभाजित कर वोट ठगने की योजना का मीडिया के समक्ष खुलासा करते हुए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी देश के हिंदुओं से यह अपील कर चुके हैं कि वे मुस्लिम समुदाय में फूट डालकर मुसलमानों को विभाजित करें। इसी सिलसिले की पहली कड़ी में तीन तलाक का मुद्दा उठाया गया और अब अपने ही कुछ विश्वासपात्र मीर जाफरों का इस्तेमाल कर भाजपा शिया–सुन्नी समाज के मध्य फूट डालने की एक बड़ी योजना तैयार कर रही है। इस काम के लिए भाजपा को वसीम रिजवी नामक एक ऐसा मोहरा मिल गया है जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन वक्फ मंत्री आजम खान द्वारा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। इस व्यक्ति ने चेयरमैन बनने के बाद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपने पद का भरपूर दुरुपयोग करते हुए लखनऊ,इलाहाबाद व रामपुर सहित कई शहरों में शिया सेंट्रल वकफ बोर्ड के अंतर्गत् आने वाली संपत्तियों को खुर्द–बुर्द कर बड़ा भ्रष्टाचार किया था। इसके विरुद्ध कई मुकद्दमे भी लंबित हैं तथा जांच भी चल रही है। समाजवादी पार्टी के समय का नियुक्त यह व्यक्ति अभी तक उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार की आंखों का भी तारा बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि भाजपा इस शिया समुदाय से संबंध रखने वाले अपने मोहरे से कभी यह वक्तव्य दिलवाती है कि शिया वक्फ बोर्ड रामजन्म भूमि मंदिर निर्माण हेतु जमीन देने को तैयार है तो कभी वसीम रिजवी को भारतीय मदरसों में आईएसआईएस के आतंकवादी शिक्षा लेते दिखाई दे जाते हैं और वह देश के सभी मदरसों को बंद करने संबंधित पत्र प्रधानमंत्री को लिखता है तथा गोदी मीडिया इस पत्र का भरपूर प्रचार भी करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष में मदरसों का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना होने के बावजूद यहां स्थानीय मुस्लिम नागरिकों का कभी भी कोई ऐसा संगठित राष्ट्रव्यापी आतंक नजर नहीं आया जिसकी तुलना हम भारत में सक्रिय उन आतंकवादी संगठनों से कर सकें जिन्होंने हमारे देश,समाज यहां तक कि आम लोगों के जनजीवन को समय–समय पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित किया है। यदि हम कश्मीर,उसकी भौगोलिक संरचना,उसके राजनैतिक दांव–पेंच तथा भारत–पाक कश्मीर तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य चल रहे अलग–अलग नजरियों की बात छोड़ दें तो मुसलमानों से संबंधित कोई भी आतंकी संगठन देश के अन्य किसी राज्य में कभी सक्रिय नहीं रहा। हां सीमापार से भेजे जाने वाले आतंकियों ने देश में कश्मीर से लेकर मुंबई तक कई बड़े आतंकी हमले जरूर किए हैं। परंतु जहां तक मदरसों से आतंकवादी निकलने का प्रश्न है तो वसीम रिजवी को यह भी बताना चाहिए कि देश में दशकों से सक्रिय माओवादी संगठन आखिर किन मदरसों से तालीम हासिल करते रहे हैं? देश में सक्रिय रहे खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट,सिख यूथ फेडरेशन,युनाईटेड लिबरेशन फ्रुट ऑफ आसाम (उल्फा)नेशनल डेमोक्रटिक फ्रंट बोडोलैंड, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी,ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स,पीपुल्स वॉर ग्रुप तथा इससे संबंधित अनेक माओवादी संगठन, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर व इससे संबंधित अनेक संगठन,लिबरेशन टाईगर्स आफ तमिल ईलम(लिट्टे),मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट,बब्बर खालसा इंटरनेशल,खालिस्तान कमांडों फोर्स,तमिल नेशलन रिट्रविल ट्रुप्स तथा अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज जैसे 32 संगठन जिन्हें केंद्र सरकार विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण)अधिनियम 2004 के तहत भारत सरकार प्रतिबंधित कर चुकी है इनसे जुड़े आतंकी आखिर किन मदरसों से शिक्षा लेते रहे हैं?

वसीम रिजवी को यह भी बताना चाहिए कि सुनील जोशी,संदीप डांगे,लोकेश शर्मा,स्वामी असीमानंद,राजेंद्र समुंद्र,मुकेश वासवानी,देवेंद्र गुप्ता,चंद्रशेखर लेवे,कमल चौहान,रामजी काल संगरा, कर्नल श्रीकांत पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे समझौता एक्सप्रेस कांड, अजमेर शरीफ दरगाह,मालेगांव तथा मक्का मस्जिद ब्लास्ट में शामिल आतंकवादी आखिर किन मदरसों की देन हैं? मदरसों को लेकर भय फैलाने की सियासत करने वालों को यह भी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी,इंदिरा गांधी,राजीव गांधी,ललित नारायण,हरचरण सिंह लौंगोंवाल,सरदार बेअंत सिंह,हरेन पांडया,गौरी लंकेश,कलबुर्गी,पंसारे और अब ताजा प्राप्त हो रहे समाचारों के अनुसार गोपी नाथ मुंडे जैसे अनेक लोगों के हत्यारे आखिर किन मदरसों से शिक्षा लेकर आए थे?स्पष्ट है कि भाजपा जिन मोहरों व चालों का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए कर रही है उससे साफ जाहिर होता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव बांटों और राज करो की राह पर आगे बढ़ रहा है।

–यह लेखक के निजी विचार है।

अंगूठा छाप और माफिया चला रहे हैं स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी...

'समाज कल्यांण विभाग के जरिए किए जाने वाले इस घपले में शिक्षण संस्थानों के संचालकों की ही नहीं, बैंक प्रबंधकों की भी बड़ी भूमिका रहती है क्योंकि उनकी मिलीभगत के बिना न तो छात्रों के फर्जी खाते खुल पाना संभव है और न उनके नाम पर पैसा निकल पाना। यूं तो सरकार से छात्रवृत्ति मिलने का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें हर वर्ग के छात्रों को लाभान्वित किया जाता है किंतु आईटीआई, पॉलीटेक्निक, बीएड व अन्य टीचर्स ट्रेनिंग के लिए सरकार काफी पैसा देती है और यही पैसा हर साल शिक्षा माफिया की जेबें भरता है।'

सुमित्रा चतुर्वेदी, मथुरा

जी हां! बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा और बहुत से लोग यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कृष्ण की नगरी में एक ओर जहां अंगूठा छाप लोग और माफिया स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी चला रहे हैं वहीं दूसरी ओर मिस्त्रि यों के हाथ में ग्रुप ऑफ इंस्टी्ट्यूट की कमान है।

आज हर किस्म की शिक्षा का हब कहलाने वाले इस धार्मिक जनपद में वर्ष 1997 से पहले न तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था और न अन्यं किसी किस्म का तकनीकी शिक्षण संस्था न।

1997 में अग्रवाल शिक्षा मंडल ने बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, हालांकि आज अग्रवाल शिक्षा मंडल बड़े विवादों से घिरा हुआ है और उसके प्रबंधतंत्र में शामिल रहने वाले लोग लगातार उसकी जड़ खोद रहे हैं। बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के बाद मथुरा ने शिक्षा के क्षेत्र में जो करवट ली, उसी का परिणाम है कि आज यह धार्मिक जनपद न केवल हर किस्मे की शिक्षा का हब कहलाने लगा है बल्कि प्रदेश ही नहीं, देशभर में अलग पहचान रखता है।

स्याह पहलू

दरअसल, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पैर फैलाने तथा शिक्षा जगत का पूरी तरह निजीकरण हो जाने पर इसमें ऐसे–ऐसे तत्वोंर ने प्रवेश करना शुरू कर दिया जिनकी गिनती इससे पहले माफियाओं में होती थी और जिनका शिक्षा से दूर–दूर तक कभी वास्ता नहीं रहा। यही वो दौर भी था जब तकनीकी शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए फीस के अलावा कैपिटेशन फीस अथवा डोनेशन के नाम पर भारी–भरकम रकम देनी होती थी। डोनेशन के इस खेल ने शिक्षा के कारोबार में उतरे बेपढ़े–लिखे लोगों तथा माफियाओं को वो स्था यित्वन प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीओट्यूट की लाइन लग गई। जो मथुरा कभी सिर्फ कृष्णा की पावन जन्मस्थली, यमुना के तीर्थ विश्रामघाट एवं द्वारिकाधीश, बिहारीजी और गिर्राज जी के कारण पहचाना जाता था, वह तकनीकी शिक्षा के लिए भी पहचाना जाने लगा।

इज्जत, दौलत और शौहरत एकसाथ

एक साथ इज्जत, दौलत और शौहरत दिलवाने वाले इस कारोबार ने सर्वाधिक आकर्षित ऐसे तत्वों को किया जिन्होंने विभिन्न माध्यम से पैसा तो बहुत कमा लिया था किंतु प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। जाहिर है कि इन तत्वों् को चोला बदलने का इससे अधिक सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला था अतः इन्होंने भारी–भरकम निवेश करके बड़े–बड़े शिक्षण संस्थान खोल लिए। आज मथुरा जनपद में चारों ओर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की जो श्रृंखला दिखाई देती है, उनका संचालन अधिकांशतः ऐसे ही तत्व कर रहे हैं। किसी समय देश को हिला देने वाले स्टांप घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी से जुड़े व्यक्ति ही नहीं, वो लोग भी आज मथुरा में शिक्षण संस्थान संचालित कर रहे हैं जिनके परिजनों की शिनाख्त ही कभी नाम के साथ तस्कर लगाकर कराई जाती थी। कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना किसी को बुरा नहीं लगता। शिक्षा जगत में आए इस बूम का लाभ उन तत्वों ने भी उठाया जिन्हें मथुरा के तमाम लोगों ने एक अटैची में पेचकस, प्लास तथा कटर आदि लेकर चलते देखा था और जो ऑफिस–ऑफिस जाकर कम्प्यूटर की रिपेयरिंग या अधिक से अधिक उसके हार्डवेयर संबंधी दिक्केतें दूर किया करते थे।

माफिया की घुसपैठ कैसे और क्यों

शिक्षा माफिया, समाज कल्यामण विभाग तथा बैंकों की मिलीभगत से आज ऐसे लोग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के मालिक बने बैठे हैं। ये बात और

है कि आज भी इनमें से कई को अपना चेक साइन करने में तीस सेकंड से भी अधिक का समय लग जाता है तो कोई बमुश्किल कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर पाता है। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कैपिटेशन फीस अथवा डोनेशन की वसूली पर लगाम लगाने तथा अवैध तरीकों से छात्रों का आर्थिक शोषण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किए जाने के कारण निःसंदेह शिक्षा व्यवसाय की आमदनी के स्त्रोत कुछ घटे हैं परंतु छात्रवृत्ति तथा प्रतिपूर्ति के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पने का खेल अब भी लगातार जारी है।

छात्रवृत्ति घोटाला

शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति के नाम पर प्रतिवर्ष सरकार को अरबों रुपए का चूना लगा देने का मामला कई बार विधानसभाओं और यहां तक कि संसद में भी उठ चुका है लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण इस खेल पर रोक नहीं लग पा रही है।

समाज कल्यांण विभाग के जरिए किए जाने वाले इस घपले में शिक्षण संस्थानों के संचालकों की ही नहीं, बैंक प्रबंधकों की भी बड़ी भूमिका रहती है क्योंकि उनकी मिलीभगत के बिना न तो छात्रों के फर्जी खाते खुल पाना संभव है और न उनके नाम पर पैसा निकल पाना। यूं तो सरकार से छात्रवृत्ति मिलने का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें हर वर्ग के छात्रों को लाभान्वित किया जाता है किंतु आईटीआई, पॉलीटेक्निक, बीएड व अन्य टीचर्स ट्रेनिंग के लिए सरकार काफी पैसा देती है और यही पैसा हर साल शिक्षा माफिया की जेबें भरता है।

बताया जाता है कि यदि सरकार इस क्षेत्र में शिक्षा देने वाले संस्थानों के सिर्फ छात्रों की गणना ही करवा ले तो अरबों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा क्योंकि इनके द्वारा दर्शायी गई छात्रों की संख्या और वास्तविक छात्रों की संख्या में भारी अंतर रहता है। ऐसा नहीं है कि यह खेल केवल इसी दायरे में सिमटा हो, इसका दायरा बहुत बड़ा है और इसीलिए इसमें कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट ही नहीं यूनिवर्सिटी के संचालक भी लिप्त हैं।

एक ही कैंपस में तीन–तीन पैथी के कॉलेज

मथुरा की एक यूनिवर्सिटी तो नियमों के विपरीत एक ही कैंपस से तीन–तीन पैथी के कॉलेज संचालित कर रही है लेकिन न कोई देखने वाला है और न सुनने वाला, क्योंकि मालिकों को राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। वैसे कोई बड़ा शिक्षण संस्था न ऐसा नहीं है जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्ति न हो, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है वो मीडिया से संरक्षण प्राप्त कर लेता है इसलिए सभी के काले कारनामे दबे रह जाते हैं।

राजनेता भी लिप्त

इसके अलावा कुछ शिक्षण संस्थाओं के संचालक तो बाकायदा राजनीति के क्षेत्र में हैं और चुनाव भी लड़ते हैं इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ता। यदि बात करें इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की, तो उसका भी आंकलन आसानी से किया जा सकता है। खुद को शिक्षाविद कहने वाले इन लोगों द्वारा शिक्षा जगत को दिलाई गई उपलब्धि मात्र इतनी है कि नंबर ऑफ शिक्षण संस्थाओं के मामले में मथुरा काफी आगे निकल चुका है। इससे अधिक उपलब्धि की बात करें तो वो उनकी निजी है, शिक्षा जगत के लिए नहीं।

कैंपस प्लेसमेंट में धोखाधड़ी

कैंपस प्लेसमेंट के नाम पर छात्रों को धोखा देना तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करना तो काफी आम है, और यही कारण है कि छात्र डिप्रेशन

के शिकार होकर आत्मघाती कदम उठाने से नहीं डरते।

फैकल्टी के नाम पर

इसी प्रकार योग्य फैकल्टी का अभाव या अस्थाई फैकल्टी से काम चलाना भी छात्रों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं किया जाता। शिकायत करने वाले छात्रों को प्रबंध तंत्र के कोप का शिकार बनना पड़ता है और मौजूदा फैकल्टी भी उसे फिर प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।

इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा जगत की यह दुर्दशा केवल मथुरा तक सीमित नहीं है और न अंगूठा छाप और माफिया का शिक्षा जगत पर कब्जा कोई नई बात रह गई है परंतु यह जरूर कह सकते हैं कि मथुरा में ऐसे तत्वों की संख्या दूसरे जनपदों से काफी आगे है क्योंकि यहां शिक्षा व्यूवसाय का ग्राफ मात्र दो दशक में इतना ऊपर चढ़ा है जितना दूसरा कोई व्यवसाय नहीं चढ़ पाया। माना कि किसी दूसरे व्यवसाय की तरह अनपढ़ एवं जाहिल लोगों का शिक्षा जगत में उतरना एक व्यवस्थागत दोष है और उसे उचित व्यवस्था करके ही दूर किया जा सकता है लेकिन अभिभावक चाहें तो अपने स्तर से इस पर काफी हद तक लगाम लगा सकते हैं।

भव्य कैंपस और आकर्षक प्रचार

वो चाहें तो किसी शिक्षण संस्थान को उसके भव्य कैंपस एवं आकर्षक प्रचार से न आंककर उसकी वास्तविक स्थिति से आंक लेने के बाद एडमिशन का निर्णय ले सकते हैं क्योंकि यही वह तरीका है जिससे बच्चों का भविष्य् अंधकार मय होने से बचाया जा सकता है तथा शिक्षा व्यवसाइयों को भी आइना दिखाया जा सकता है अन्यथा न तो छात्रों द्वारा आत्म हत्या के मामलों में कमी आएगी और न उनकी संदिग्ध मौतों में।

छात्रों की अकाल मौत

छात्रों को अकाल मौत से बचाना है तो स्थिति की गंभीरता को समझना होगा, और उन परिस्थितियों को भी जिनके दायरे में रहकर छात्र ऐसे लोगों के हाथों खेलने पर मजबूर हैं जिन्हें छात्रों की मनःस्थिति से या उनके अभिभावकों की मानसिकता से कोई लेना–देना नहीं होता। उन्हें लेना–देना होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने निवेश को लाभ में बदलने से, नतीजतन पहले जहां शिक्षण संस्थान खोलना समाजसेवियों का शगल होता था वहीं आज वह नवधनाड्यों के लिए उनके सारे कारनामे छिपाने तथा इज्जत, दौलत व शौहरत एकसाथ हासिल कर लेने का जरिया बन गए हैं।

हाथरस लोकसभा सीट

भाजपा और महागठबंधन से टिकट पाने को एड़ी-चोटी के जोर लगा रहे दिग्गज

2019 की रणभेरी बज चुकी है । चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तिथियों का ऐलान कर सकता है जिसको देखते हुए राजनैतिक दलों में टिकट के लिए दावेदारी शुरू हो गयी है । अलीगढ और आगरा के बीच स्थित हाथरस लोकसभा क्षेत्र से कई दिग्गज चुनाव लड़ने को बेताब हैं । 2014 में चली मोदी लहर में भाजपा के राजेश दिवाकर ने राष्ट्रीय लोकदल से यह सीट जीती थी । यूपी में सपा–बसपा और रालोद के महागठबंधन के बाद अब एक बार फिर हाथरस लोकसभा क्षेत्र पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में है । भाजपा से वर्तमान सांसद राजेश दिवाकर अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं यह अभी भविष्य की गर्त में हैं लेकिन भाजपा से टिकट के लिए तमाम दिग्गज दावेदारी कर रहे हैं ।

वहीँ महागठबंधन से भी सपा और रालोद के कई धुरंधर टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं । दरअसल रालोद हाथरस लो. कसभा क्षेत्र पर अपनी दावेदारी कर रहा है । चूँकि जाट बाहुल्य इगलास और सादाबाद विधानसभा क्षेत्र हाथरस में ही हैं इसलिए राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी मजबूत है । वहीँ सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मत्री रामजीलाल सुमन हाथरस से ही हैं और वह गत चुनाव में दूसरे नंबर पर थे इसलिए वह भी सपा के खाते में हाथरस को लाने के लिए प्रयासरत हैं । चर्चाएँ यह भी चलीं कि रालोद के सिम्बल पर रामजीलाल सुमन चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन अधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है । रालोद के सूत्रों का कहना है कि हाथरस पर रालोद चुनाव लडेगा और प्रत्याशी भी रालोद का ही होगा । रालोद से टिकट पाने के लिए पूर्व मंत्री चौ महेंद्र सिंह, दिल्ली के समाजसेवी नरेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक खैर भगवती प्रसाद सूर्यवंशी, पूर्व विधायक हाथरस गेंदालाल चौधरी, पूर्व विधायक त्रिलोकीराम दिवाकर, एडवोकेट फूल सिंह धनगर, रालोद नेता सीपी सिंह धनगर जैसे दिग्गज जोर अजमाइश कर रहे हैं । रालोद के दावेदार दिल्ली तक छोटे चौधरी अजित सिंह एवं रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी तक अपनी गोटियाँ बिछाने में जुटे हुए हैं ।

सत्ताधारी भाजपा से वर्तमान सांसद राजेश दिवाकर के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान, इगलास विधायक राजवीर दिलेर की पुत्री मंजू दिलेर, अतुल बाल्मीकि, रामवीर भैयाजी टिकट की लाइन में हैं । वहीँ प्रियंका के आने से उत्. साहित कांग्रेस से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे राजेश राज जीवन ताल ठोक रहे हैं ।

हाथरस पर 2019 में किसकी विजय पताका लहराएगी और किस्मत का ताला खुलेगा यह भविष्य बताएगा लेकिन इतना निश्चित है कि हाथरस पर चुनाव बहुत ही रोचक होगा ।

गडकरी के बयान की गंभीरता को समझे नेता

▸ तारकेश्वर मिश्र

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के वादे पूरे नहीं करने पर पिटाई वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि गडकरी का बयान भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलता के प्रति उठते आवाज को दर्शाता है। वहीं, भाजपा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दल को बेनकाब किया है। गडकरी ने बीते रविवार को मुंबई में एक समारोह में कहा था कि जो नेता जनता से बड़े–बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं करते तो जनता उन्हें पीटती भी है। उन्होंने यहा भी कहा कि वह काम करते हैं और जनता से किए गए वादे पूरे किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान चर्चाओं में है कि वायदे वही करो जिन्हें पूरा कर सको वरना जनता पीटेगी। श्री गडकरी उन चंद राजनेताओं में से हैं जो काम करने के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री के तौर पर उनके काम की देश भर में प्रशंसा हुई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उन्हें गंगा सफाई, सड़क, पुल, फ्लाईओवर, हाइवे और बंदरगाह बनाने जैसे काम वाला मंत्रालय दिया गया और पाँच साल पूरे होते–होते वे ही ऐसे मंत्री हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड उन्हें 90 फीसदी अंक देता है। उनके ताजा बयान को प्रधानमंत्री पर कटाक्ष के रूप में लिया जा रहा है। राजनीति का विश्लेषण करने वालों के अनुसार श्री गडकरी की नजर चुनाव बाद के सियासी हालात पर है।

चुनाव जीतने के बाद मानव नेता की आत्मा ही बदल जाते हैं आप जिस नेता को जिताने के लिए अपना दिन रात एक कर के उसके प्रचार–प्रसार में लगे रहते थे वही नेता आपको घास भी नहीं डालता और अपने वादों को ऐसे भूल जाता है जैसे वादे कभी किए ही नहीं थे आप नेता से मिलने का प्रयास भी करते हैं लेकिन आपको मिलने नहीं दिया जाता और गलती से आप मिल भी जाते हैं तो आप को फिर से किसी ना किसी प्रकार के झूठे आश्वासन देकर भेज दिया जाता है और यह चीज फिर अगले चुनावों में दोहराई जाती है फिर से आ तो वही नेता या कोई और नेता भी झूठी बातें वही झूठे वादे और आम जनता को बेवकूफ बना और हर बार नेता से आस लगा के रखना इस बार तो है ना लेकिन कभी आता नहीं है ना कभी होता है। हालिया चुनाव

चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से झूठे वादे करने वाले राजनीतिक दलों के मुखियों उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाने चाहिए। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नेता लोग जनता से झूठे वादे करके सत्ता का सुख लेते हैं लेकिन किए हुए वादे नहीं निभाते। चुनाव आयोग को ऐसे नेताओं पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाना चाहिए।

पूर्व सर्वेक्षणों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में यद्यपि एनडीए सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा लेकिन उसे बहुमत नहीं मिलेगा और उस सूरत में श्री मोदी की बजाय श्री गडकरी के नाम पर बाहरी समर्थन बटोरकर सरकार बनाई जा सकेगी। लोकसभा चुनाव के पहले दिए उनके ताजा बयान को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वह एक संदेश है सभी राजनीतिक दलों के लिए जो चुनाव जीतने के लिए ऐसे–ऐसे वायदे कर देते हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता और उसकी वजह से जनता के मन में गुस्सा तो बढ़ता ही है उससे भी ज्यादा राजनीति के बारे में अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है।

1971 के लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के भीतर संकट से घिरी इंदिरा जी ने जनताा के बीच जा–जाकर कहा कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ और विपक्षी कहते हैं इंदिरा हटाओ। देश की जनता ने उनकी बात पर भरोसा करते हुए उन्हें प्रचंड बहुमत दे दिया। लेकिन गरीबी हटना तो दूर अब तो गरीबी रेखा से नीचे वाली श्रेणी भी अस्तित्व में आ गई। यही हाल रोजगार का है। केंद्र की सत्ता में आई हर सरकार ने बेरोजगारी मिटाने का वायदा तो किया किन्तु उसे पूरा करने में विफल रही। किसानों के साथ किये गए वायदे भी हवा–हवाई होकर रह गए। आज देश में जो अविश्वास और चौतरफा असन्तोष का वातावरण है उसका सबसे बड़ा कारण चुनावी वायदे पूरे न होना ही है। आजकल किसानों के कर्ज माफ किया जाना चुनाव जीतने का नुस्खा बन गया है। लेकिन सत्ता में आने के बाद उसे पूरा करने में तरह–तरह की परेशानियां आती हैं जिससे किसानों में गुस्सा बढ़ता है।

हमारी सरकार और उनके वादे?

हमारा देश एक लोकतान्त्रिक देश है. यहाँ सबको अपना स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है. यहां सब लोग स्वतन्त्र है। पर दुखः इस बात का है कि हमारे देश मै आज भी आदे से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। हमारे देश मे साक्षरता भी निम्न है। बेरोजगारी भी बढ़ रही है आज दुनियां के देश विकसित है। और हमारा देश विकाशील ऐसा क्यों? हमारे देश मे प्रति वर्ष अनेकों किसान आत्महत्या करता है क्यों? इन सबका जबाब किसी के पास नहि है यहां तक कि जो हमारी सरकार है उनके पास भी नही है हमारे देश में लगभग सवा अबर से भी ज्यादा जनसख्यां है। और इतने बड़े लोकतन्त्र देश मे हम लोग एक सही लीडर नहीं चुन सकते जो हमारे लिये बड़ी दुःख एवं शर्म की बात है। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे देश की डोर गलत सरकार के हाथो मे चली जाती है। और जिसका परिणाम हमे ही भुगतना पड़ता है।

गडकरी जी के जिस बयान पर दो दिनों से बवाल मचा है उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने सत्ता में आने के बाद हर व्यक्ति को न्यूनतम आय देने का वायदा करते हुए कह दिया कि उनके खाते में प्रति माह एक निश्चित राशि जमा कर दी जावेगी। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार तीन दिन बाद पेश किए जाने वाले बजट में ऐसा ही प्रावधान करने वाली है। इसी के साथ किसानों के खाते में भी हर फसल के पहले तय रकम जमा करने का प्रावधान भी अपेक्षित है। गरीब लोगों को मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी के एवज में राशि उनके बैंक खाते में जमा किये जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यदि वाकई मोदी सरकार ऐसा करती है तब उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य लोकसभा चुनाव जीतना होगा। राहुल ने मनरेगा की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया था। जैसे–जैसे चुनाव करीब आएंगे वायदों की टोकरी और भी भरती जावेगी। प्रश्न ये है कि उन्हें पूरा करने की गारंटी क्या है?

चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से झूठे वादे करने वाले राजनीतिक दलों के मुखियों उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाने चाहिए। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नेता लोग जनता से झूठे वादे करके सत्ता का सुख लेते हैं लेकिन किए हुए वादे नहीं निभाते। चुनाव आयोग को ऐसे नेताओं पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाना चाहिए।चुनाव आयोग के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय–समय पर चुनाव घोषणापत्र को हलफनामे के तौर पर लिए जाने की बात कही किन्तु राजनीतिक दल उसके लिए राजी नहीं हैं और आगे भी शायद ही होंगे क्योंकि उनका मकसद येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना मात्र है। यदि वे ईमानदार होते तो देश में नेताओं और राजनीति के प्रति इतनी वितृष्णा नहीं होती। उस दृष्टि से श्री गडकरी ने वायदे पूरे न होने पर जनता द्वारा पीटे जाने संबंधी जो बात कही उसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि पीटे जाने से आशय केवल सत्ता से हटाना मात्र नहीं बल्कि उसके आगे भी सम्भव है। समय आ गया है जब चुनावी वायदे करने की गारंटी का भी प्रावधान चुनाव आयोग रखे वरना राजनेताओं की पिटाई को रोकना असम्भव हो जाएगा। आखिर सहनशक्ति की भी कोई सीमा होती है। कानून में प्रावधान है कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और धोखा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हैरानीजनक है कि हर पांच वर्षों के बाद राजनीतिक पार्टियां के नुमाइंदे झूठे चुनावी वायदे करते हैं और लोगों से किए वादे नहीं निभाते। उन्होंने वोटरों से अपील की है कि वह ऐसे नेताओं के खिलाफ संघर्ष के लिए मैदान में आएं। गडकरी ने जो कहा उसका राजनीतिक निहितार्थ तो लोगों ने निकाल लिया लेकिन उसमें जो व्यवहारिक और सामयिक चेतावनी है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा और यही हमारी देश की सबसे बड़ी विडंबना है।

– यह लेखक के निजी विचार है।

जार्ज जैसे नेता विरले ही होते हैं

▶ अवधेश कुमार

जार्ज फर्नांडिज को इस रुप में तो याद किया ही जाएगा कि वो नौ बार लोकसभा चुनाव जीते तथा तीन सरकारों में मंत्री रहे। किंतु जार्ज जैसे संघर्षशील योद्धा को केवल इस रुप में याद करना उनके साथ न्याय नहीं होगा। एक सांसद और मंत्री के नाते उनके कार्य हमेशा उल्लेखनीय रहे, उन्होंने अनेक साहसी निर्णय किए, लेकिन जार्ज मूल रुप से एक आंदोलनकारी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले ऐसे नेता थे जिनको देश भर का कामगार अपना मानता था। जीवन के लंबे समय तक राजधानी दिल्ली के 3 कृष्णमेनन मार्ग वाला उनका आवास कितने आंदोलनों के मुख्यालय जैसा था।

उनमें कई ऐसे आंदोलन थे जिसे सरकार में रहते हुए समर्थन करना मुश्किल था, लेकिन जार्ज ने कभी उनको बाहर नहीं किया। म्यान्मार में सैनिक जुंटा के खिलाफ भारत से संघर्ष करने वाले भी वहां मिलते थे तो भूटान और नेपाल के आंदोलनकारी भी। तिब्बत मुक्ति संग्राम के लोग तो उनमें अपना नेता देखते ही थे। मंत्री रहते हुए भी जार्ज का दरवाजा आम आदमी के लिए कभी बंद नहीं हुआ। रक्षा मंत्री रहते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई, पर सुरक्षा कर्मियों को हिदायत थी कि सुरक्षा चेक के अलावा ज्यादा प्रश्नों से किसी को परेशान न किया जाए। उनके व्यक्तित्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नरसिंह राव सरकार में गृहमंत्री एस बी चव्हाण उनके बगल में रहते थे। जब भी उनको निकलना होता आसपास के आवासों का गेट सुरक्षाकर्मी काफी पहले बंद कर देते थे। जार्ज ने पहले इसका विरोध किया, ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं खड़ा होकर गेट ही तोड़कर हटा दिया। लंबे समय उनके आवास पर गेट था ही नहीं। अटलबिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान रक्षा मंत्री बनने पर जब सुरक्षा समस्या आई तो काफी दबाव पर उनके आवास पर गेट लगा।

सच कहा जाए तो भारतीय राजनीति में जार्ज अपने किस्म के अकेले नेता थे। उनके पास औपचारिक शिक्षा की बड़ी डिग्री नहीं थी लेकिन वो एक साथ अनेक भाषाओं के जानकार थे। यह शायद कम लोगों को पता हो कि वे संस्कृत के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। आपाताकल में जब वे तिहाड़ जेल में बंद थे तो अपने साथियों का आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए श्रीमद्भगवतगीता पढ़कर सुनाया करते थे। विचार से समाजवादी, धर्म से ईसाई का गीता पढ़कर सुनाना सामान्य बात नहीं है। आपातकाल विरोधी संघर्ष ने उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि 1977 में उन्हें बिहार के मुजफ्फरपुर से जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। वे जेल में थे। उनका एक पोस्टर चारों ओर लगा था जिनमें हथकड़ी से बंधे उनके हाथ थे और लिखा था, ये हथकड़ी मुझे नहीं, लोकतंत्र को जकड़े हुए है। मुजफ्फरपुर में उंगली पर गिने हुए लोगों ने तब तक उन्हें देखा होगा, पर बिना उनके गए जिता दिया। विजय होने के बाद जब वे जेल से छूटे तब मुजफ्फरपुर गए। साफ दिल वाले, निर्भीक और साथ मस्त नेता के रुप में हम उनको याद करते थे।

कर्नाटक के मैंगलोर के ईसाई परिवार में पैदा हुआ एक लड़का जिसे 16 वर्ष की उम्र में पादरी बनने के लिए भेजा जाता है, वह वहां से निकलकर मुंबई आ जाता है और कुछ ही वर्षों में वहां का सबसे बड़ा मजदूर नेता बन जाता है। यह सामान्य बात नहीं है। 1950 से 60 के बीच तबके बॉम्बे में छोटे–बड़े इतने हड़ताल उन्होंने कराई कि अखबारों में पढ़कर लोग सोचते थे कि एक बार जार्ज को देखना

चाहिए। उस दौरान न जाने कितनी बार उन्हें जेल जाना पड़ा, पुलिस ने कई बार उन्हें जमकर पीटा, वे घायल हुए और अस्पताल तक में भर्ती हुए। किंतु संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। वहां उनकी लोकप्रियता इतनी हो गई कि 1967 के आम चुनाव में दक्षिण बॉम्बे से लोगों ने कांग्रेस के कद्दावर नेता एसके पाटिल को हराकर उन्हें सांसद बना दिया। जार्ज का चुनाव वहां के ड्राइवरों से लेकर ठेले, खोमचे वालों, अलग–अलग मजदूर संघों का चुनाव था। वे ही खर्च पूरा करते थे और चुनाव प्रबंधन भी। आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेल हड़ताल कराने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। 8 मई 1974 को ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के अध्यक्ष के नाते उनके हड़ताल का व्यापक असर हुआ। देशभर की रेल व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। यह हड़ताल केवल रेलवे तक सीमित नहीं रहा। देश के अनेक विभागों के कर्मचारी संघों का समर्थन मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के लिए इससे निपटना कठिन हो गया था। सरकार ने हड़ताल को कुचलने की नीति अपनाई। जगह–जगह पुलिस ने हड़तालियों की पिटाई की, गिरफ्तारियां की। मोटा–मोटी आंकड़ा यह है कि 30 हजार से ज्यादा लोग इस दौरान गिरफ्तार हुए।जार्ज अब पूरी तरह सरकार और सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर आ गए थे। देश में आपातकाल लगाने की सोच जिन कारणों से उभरी उसमें जार्ज के आह्वान पर आयोजित हड़तालों से पैदा हुई स्थितियां भी थीं। उससे प्रेरित और प्रभावित हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कहीं न कहीं चलते ही रहे। जार्ज पर देशद्रोह का भी आरोप लगा। उसके बाद आपातकाल लग गया और पुलिस देश भर में जार्ज को पकड़ने के लिए छापे मारती रही। बाद में पता चला कि वो सिख की वेशभूषा में घूमते थे और कई जगह पूछे जाने पर स्वयं को खुशवंत सिंह बता देते थे। हालांकि अंततः वे पकड़े गए और तिहाड़ जेल में उन्हें रखा गया। जार्ज की विचारधारा समाजवादी अवश्य थी, लेकिन उनका आचरण अनेक बार समाजवाद की मान्य परिधि से बाहर जाता था। इसलिए उनको समाजवादी कहते हुए भी हमें एक स्वतंत्रचेत्ता व्यक्तित्व मानना होगा। उनका चरित्र स्पष्ट बोलने का था। संघ, जनसंघ और भाजपा का एक समय उन्होंने विरोध किया, लेकिन कई बार हड़ताल और संघर्ष में इनका साथ भी लिया। वैचारित मतभेद रखते हुए भी उन्होंने राजनीतिक अस्पृश्यता को अपने साथ फटकने नहीं दिया। इस कारण उन्हें अपने साथियों की उलाहनाएं भी सुननी पड़ती थी।

जब लालू यादव के खिलाफ लड़ने की स्थिति पैदा हुई तो उन्होंने अलग पार्टी बनाई एवं भाजपा के साथ हाथ मिलाया। केन्द्र की भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होने जो कुछ किया और जो वक्तव्य दिए वे मूल समाजवाद से कई बार मेल नहीं खाते थे। आप उनके रक्षामंत्री के कार्यकाल पर सेना के जवानों से बात करिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह उन्होंने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया था। स्वयं उनके बीच जाते थे, उनके साथ समय बिताते थे, उनकी समस्यायें सुनकर उसका निदान करने की कोशिश करते थे। पोकरण नाभिकीय विस्फोट के समय रक्षा मंत्री वही थे। जब इसकी आलोचना हुई तो वे पूरी तरह पक्ष में खड़े हुए। करगिल युद्ध उनके कार्यकाल में ही हुआ। वे लगातार युद्धक्षेत्र में जाते रहे। वे पहले रक्षा मंत्री थे जिन्होंने रिकॉर्ड 30 बार सियाचिन का दौरा किया। पूर्वोत्तर की सीमाओं पर वो सबसे ज्यादा बार गए। उन्होंने जब यह कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरा हमें चीन से है और हमारी रक्षा तैयारियां इसे ध्यान में रखकर हो रहीं हैं तो कुछ लोगो ने तूफान खड़ा करने की कोशिश की। वे अपने बयान पर कायम रहे। कई बार ऐसा कहा और इसे समझाया भी।

हालांकि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जार्ज जैसे ईमानदार और सतत् संघर्षशील नेता को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरा गया। पहले तहलका स्टिंग जिनमें उनका नाम कहीं नहीं आया, पर विपक्ष ने हमला बोलकर उनका संसद में बहिष्कार करना आरंभ किया। हारकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को उनसे कुछ समय के लिए इस्तीफा तक लेना पड़ा। उन पर ताबूत घोटाले का भी आरोप लगाया गया। यह बात अलग है कि उच्चतम न्यायालय ने 2015 में अपने फैसले में साफ कर दिया कि ताबूत घोटाला हुआ ही नहीं। यह वर्तमान राजनीति की त्रासदी ही है कि जिस जार्ज फर्नांडिस ने अपना पूरा जीवन आम आदमी और देश के लिए लगा दिया उनको उनकी पार्टी ने ही वर्षों से निराश्रित छोड़ दिया था। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार की कभी चिंता नहीं की, अंतिम समय में जब वे अल्जाइमर सहित कई बीमारियों से ग्रस्त हो गए, परिवार के सहारे के लिए विवश हो गए। हालांकि जार्ज के साथ संघर्ष से पैदा हुए उतने बड़े कद का आम आदमी के लिए सर्वसुलभ नेताओं की पीढ़ी लगभग खत्म हो रही है। देश भर ऐसे दो–चार और बचे हैं।

जो भी हो आज जो गैर राजनीतिक या राजनीतिक संघर्ष की स्थिति है उसमें जार्ज जनहित और देशहित के लिए काम करने वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। एक 16 वर्ष का किशोर बिना किसी आधार के मंबई पहुंचता है, फुटपाथ पर जीवन बिताते हुए संघर्ष एवं बदलाव की दृष्टि से देश के इतिहास का अध्याय लिखने में सफल हो जाता है तो कोई भी ऐसा कर सकता है। बस, आवश्यकता संवेदना, सोच, संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति का है।

– यह लेखक के निजी विचार है।

यूनिवर्सिटी, कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में हो रहा है महिलाओं का यौन शोषण

▸ सुरेन्द्र चतुर्वेदी

यौन शोषण के खिलाफ महिलाओं के एक वर्ग द्वारा शुरू किया गया #metoo अभियान बेशक बॉलीवुड एवं राजनीति सहित कॉर्पोरेट जगत में भी काफी चर्चित रहा तथा कई नामचीन हस्तियों को बेनकाब करने में कामयाब हुआ, किंतु उन स्थानों से फिलहाल दूर है जिन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और जिनके ऊपर देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं को तैयार करने की जिम्मेंदारी है।

यही कारण है कि धार्मिक नगरी के रूप में विश्वविख्यात मथुरा के कई निजी शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों सहित छात्राओं तक का यौन शोषण किए जाने की जानकारी मिली है।

विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मथुरा–भरतपुर रोड पर स्थित शिक्षा के कुछ ऐसे ही मंदिरों में महिला कर्मचारियों तथा छात्राओं के यौन शोषण का खेल लंबे समय से चल रहा है।

बताया जाता है कि कई–कई शिक्षण संस्थाओं का संचालन करने वाले एक ऐसे ही व्यक्ति की किसी पीड़ित फीमेल कर्मचारी ने ही पिछले दिनों वीडियो क्लिप तैयार की है।

कॉलेज की इस फीमेल कर्मचारी का कहना है कि वह संस्थान में कार्यरत दूसरी महिलाओं तथा छात्राओं के सहयोग से शीघ्र ही शिक्षण संस्थान के मालिक का घिनौना चेहरा सामने लाएगी और कानूनी कार्यवाही करेगी ताकि शिक्षा व्यवसाइयों का पर्दाफाश हो सके।

इस महिला का यह भी कहना है कि वह अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के अलावा दूसरी महिलाओं और छात्राओं के साथ लंबे समय से किए जा रहे दुष्कर्म को भी सार्वजनिक करेगी जिससे कि शिक्षा व्यवसाई को किसी एक महिला पर कीचड़ उछालने का मौका न मिले।

पीड़ित महिला का दावा है कि मथुरा–भरतपुर रोड पर शिक्षण संस्थाएं चलाने वाले इस व्यक्तिओ को संस्था्न खुलने से लेकर बंद होने तक अपने कार्यालय में एक खास महिला कर्मचारी के साथ बैठे देखा जा सकता है। यह वही महिला है जिसके इस शिक्षा व्यवसाई से संबंध संदिग्ध बताए जाते हैं और जिसे लेकर उसके सभी शिक्षण संस्थानों में चर्चा का बाजार गर्म रहता है।

संस्थान के सूत्र बताते हैं कि कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ–साथ छात्र–छात्राओं के बीच भी संचालक के रंगीन मिजाज एवं रंगरेलियां मनाने के किस्सें चर्चित हैं किंतु आदत से मजबूर संचालक पर फिलहाल कोई असर होता दिखाई नहीं देता।

सूत्रों के अनुसार महिला कर्मचारियों और छात्राओं के यौन शोषण का यह मामला सिर्फ शिक्षण संस्थाओं के अंदर तक ही

सीमित नहीं है, बाहर भी शिक्षा व्यंवसाइयों द्वारा उनका विभिन्न काम कराने के लिए उपयोग किया जाता है।

वैसे महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के साथ किए जा रहे खेल में मथुरा–भरतपुर रोड पर संचालित शिक्षण संस्थान के मालिक की संलिप्तता का यह एकमात्र मामला भी नहीं है। कई दूसरे शिक्षण संस्था के संचालक भी ऐसे घिनौने कृत्य कर रहे हैं जिनमें डीम्ड यूनिवर्सिटी तक चलाने वालों के नाम शामिल हैं। एक मामला तो पिछले दिनों अदालत तक जा पहुंचा था और फिलहाल वहां लंबित है। दूसरे मामले में स्कूंल के संचालक की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त आश्चर्यचकित कर देने वाला एक अन्य मामला 14 जनवरी 2008 के दिन तब सामने आया था जब शहर के एक नामचीन होटल के अंदर न्यायपालिका से जुड़े चार अधिकारी अलग–अलग कमरों में चार छात्राओं के साथ पकड़े गए थे।

ये छात्राएं भी एक स्थानीय तकनीकी शिक्षण संस्था् में अध्ययनरत थीं और इन्होंने पूछताछ के दौरान पुलिस को बाकायदा बताया कि शिक्षण संस्थां के मालिक ने उन्हें करियर बनाने का आश्वासन देकर अधिकारियों को एंटरटेन करने के लिए बाध्य किया था। मामला न्यायपालिका से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने उसे रफा–दफा तो कर दिया परंतु तत्कालीन जिला जज को मौके पर बुलाने के बाद, जिससे संशय की कोई गुजाइश न रहे।

जिला जज ने 20 जनवरी 2008 को एक पत्र भेजकर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा रजिस्ट्रार को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और शिक्षण संस्थान के उस मालिक का नाम भी उजागर किया जिसके बारे में छात्राओं ने स्पष्ट जानकारी दी थी। हमेशा की तरह हालांकि शिक्षण संस्था के मालिक ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर मामले को दब वा दिया परंतु तत्कालीन जिला जज का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं रजिस्ट्रार को भेजा गया पत्र असलियत सामने लाने के लिए काफी है। ऐसी ही एक डीम्डे यूनिवर्सिटी के युवा संचालक को तो कुछ समय पूर्व उनकी पत्नी ने ही संस्थान की महिला कर्मचारी के साथ देर शाम ऑफिस में रंगरेलियां मनाते रंगेहाथ पकड़ लिया था। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी के मालिक की इस घिनौनी हरकत से यूनिवर्सिटी के सभी मेल व फीमेल कर्मचारी वाकिफ हैं किंतु नौकरी पर आंच आने के डर से मुंह नहीं खोलते। यूनिवर्सिटी के दिन–प्रतिदिन गंदे होते माहौल के कारण गत दिनों कुछ लोग दूसरे संस्थानों में व्यवस्था होते ही यहां से जॉब छोड़कर जा चुके हैं।

सूत्र बताते हैं कि शिक्षा मंदिरों के संचालक और हवस के इन पुजारियों का भांडा फूटने में अब ज्याडदा समय नहीं लगेगा क्यों कि पीड़िताओं ने अब बदनामी की परवाह किए बिना उनके कुकृत्य सामने लाने का मन बना लिया है।

जो भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक विश्व विख्यात धार्मिक नगरी से एजुकेशन हब के रूप में पहचान बनाने वाली कृष्ण की नगरी आज शिक्षा के मंदिरों में किए जा रहे यौन शोषण के लिए भी बदनामी हासिल करने लगी है और इसकी चर्चा कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी कैंपस की दीवारों से बाहर तक हो रही है। इन हालातों में यदि कभी किसी सफेदपोश शिक्षा व्यवसाई का घृणित चेहरा अचानक सामने आ जाए तो आश्चर्य नहीं क्योंकि दुष्कर्म किया भले ही बंद कमरों में जाता हो परंतु उसकी दुर्गंध को ज्यादा दिनों तक दबाए रखना संभव नहीं होता।

–यह लेखक के निजी विचार है।

2019 में मोदी-शाह भाजपा की जरूरत या मजबूरी ?

देश भाजपाईयों द्वारा लोगों का राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रवाद का प्रमाणपत्र बांटे जाने के चलन को लेकर भी बहुत दुरूखी है। ऐसे में देश की नजरें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि क्या 2019 में भी भाजपा की राज्य इकाईयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उसी जोश के साथ आमंत्रित करेंगी जैसाकि 2014 में किया था? क्या 2014 की ही तरह कांग्रेस व नेहरू-गांधी परिवार के विरोध पर आधारित मोदी-शाह का भाषण 2019 में भी उन्हें उर्जा प्रदान करेगा?

दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। भाजपा सूत्रों के मुताबिक इस अधिवेशन में देशभर से लगभग 12 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन में पार्टी के मंत्री,सांसद,विधायक,पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता आदि सभी शामिल थे। इस अधिवेशन में जहां पार्टी ने राजनैतिक व आर्थिक मुद्दों पर पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव पारित किए वहीं भाजपा ने 2019 के लिए भी एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लडने का इरादा जाहिर किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण रामलीला मैदान में चारों ओर लगाए गए वह बैनर थे जिनपर साफतौर पर लिखा हुआ था–अब की बार फिर मोदी सरकार।

अपने अलग–अलग संबोधनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को भाजपा का सुनहरा भविष्य दिखाने का प्रयास करते हुए उनमें ऊर्जा व उत्साह भरने की कोशिश की गई। पिछले दिनों राजस्थान,मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद अमित शाह द्वारा कार्यकर्ताओं को यह सुनहरा सपना दिखाया गया कि– यदि 2019 में भाजपा पुनरू सत्ता में आती है तो पार्टी का परचम केरल तक लहराएगा। जो भाजपा, केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की संसदीय सीट तथा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की फूलपुर सीट नहीं जीत सकी उस भाजपा के अध्यक्ष अमितशाह ने अपने कार्यकर्ताओं से यह उम्मीद बांध रखी है कि वे इस बार उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीतने के बजाए 74 की संख्या पर पहुंचेंगे।

बहरहाल, प्रत्येक पार्टी अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई इसी प्रकार करती है ताकि उनका जोश व उत्साह कायम रह सके। भाजपा भी गत् पांच वर्षों में विभिन्न चुनावों में बार–बार मिलने वाली पराजय के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ ऐसा ही कर रही है। परंतु इन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब 2014 से लेकर अब तक मोदी व शाह की जोड़ी ने पार्टी को विभिन्न स्तरों पर काफी क्षति पहुंचाई है ऐसे में पार्टी 2019 में पुनः इन्हीं नेताओं को अगले लोकसभा चुनाव का चेहरा बनाने क्यों जा रही है? क्या पार्टी के पास इस जोड़ी के अतिरिक्त कोई दूसरा नेतृत्व नहीं है? या फिर मोदी व अमित शाह के अतिरिक्त और कोई नेता राजनीति के वर्तमान वातावरण में जूझने की क्षमता नहीं रखता? या फिर मोदी व अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन चुके हैं? अभी पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी द्वारा बार–बार कुछ ऐसे बयान दिए गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों के या तो विरुद्ध थे या उनकी राजनैतिक सोच से मेल नहीं खाते थे। गडकरी

की इस बयानबाजी को राजनैतिक विशखेषकों द्वारा बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा रहा था। उधर मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़ व राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के हाथ से निकलने के बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ की ओर से भी यह चिंतन किया जाने लगा था कि 2019 में मोदी–शाह पर विश्वास जताया जाना चाहिए या फिर इसका विकल्प तलाश करने की जरूरत है?

2014 के बाद भाजपा खासतौर पर मोदी व शाह की जोड़ी को देश ने एक अहंकारी नेतृत्व के रूप में देखा है। अपने सहयोगी घटक दलों को अपने साथ जोड़ पाने में भी पार्टी सफल नहीं रही है। उसके अपने कई सहयोगी गठबंधन छोडकर जा चुके हैं और कई साथ छोडने को तैयार बैठे हें। यशवंत सिन्हा तथा शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता हर वक्त भाजपा व नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जनता दल यूनाईटेड,शिवसेना व लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी जैसे कई सहयोगी घटक दल ऐसे भी हैं जिनकी शर्तों को मानकर अपना साथ न छोडने देना भाजपा की मजबूरी बन चुकी है। तीन राज्यों की हार के बाद पार्टी की राज्य इकाईयों के न केवल नेता व मंत्री बल्कि मुख्यमंत्री तक गुपचुप तरीके से यही कह रहे हैं कि इन राज्यों में भाजपा की हार मोदी व शाह की वजह से तथा केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों तथा नोटबंदी,जीएसटी,मंहगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों की वजह से हुई है अन्यथा राज्य की भाजपा सरकारें अपने–अपने चुनाव पुनरू जीत सकती थीं। स्वयं आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि राजस्थान,मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के जिन–जिन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाएं कीं उनमें से अधिकांश सीटों पर भाजपा को हार का ही मुंह देखना पड़ा। उधर प्रधानमंत्री व अमितशाह की सभाओं में भी लाख प्रयासों व सरकारी साधनों के दुरुपयोग के बावजूद अपेक्षित भीड़ भी नहीं आ रही थी।

जाहिर है 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव इन तीन राज्यों के चुनाव परिणामों से अछूते कतई नहीं रहेंगे। क्योंकि भाजपा नेताओं की ओर से ही यह बार–बार कहा जा रहा था कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव का सेमीफाईनल हैं। जो बाबा रामदेव 2014 में इस संकल्प के साथ अपने हरिद्वार आश्रम से बाहर निकल गए थे कि जब तक नरेंद्र मोदी को वे प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे तब तक हरिद्वार वापस नहीं आएंगे। अब वही बाबा रामदेव यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि 2019 के आम चुनाव के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा यह हम नहीं कह सकते। वैसे भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा मोदी–अमित शाह की चुनावी रणनीति में काफी अंतर नजर आ रहा है। संघ जहां चुनाव पूर्व अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने की दिशा में मोदी–शाह से कुछ सकारात्मक,रचनात्मक तथा निर्णायक कदम उठाए जाने की उम्मीद रखता है वहीं दूसरी ओर पार्टी के चाणक्य समझे जाने वाले अमितशाह तथा स्वयं को अजेय समझने वाले प्रधानमंत्री मोदी जोकि हमेशा वोट बैंक की राजनीति का विरोध करते रहे हैं अब स्वयं उसी वोट बैंक की राजनीति कर 2019 में पुनरू सत्ता में वापसी की जुगत लगा रहे हैं।

मोदी–शाह की रणनीति में सामान्य श्रेणी के लोगों को सरकारी नौ. करियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा,मुस्लिम महिलाओं को खुश करने के लिए संसद में तीन तलाक बिल पास कराना,मूर्तियों की राजनीति करना,महिला अधिकारों के विषय पर तीन तलाक व सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश में भेद करना,गाय तथा गंगा के नाम पर राजनीति करना, हिंसक भीड़ द्वारा निहत्थे लोगों की हत्याओं पर खामोश रहना,यहां तक कि बलात्कारियों व हत्यारों के समर्थन में खड़े होने वाले पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं पर नकेल कसने के बजाए उन्हें अपनी खामोशी से मूक स्वीकृति देना,शरणार्थियों के नाम पर हंगामा खड़ा करना,कांग्रेस व नेहरू परिवार को देश का दुश्मन साबित करने में अपनी पूरी उर्जा लगा देना,देश को आधुनिक तथा वैज्ञानिक युग की ओर ले जाने के बजाए पौराणिक व काल्पनिक युग में ले जाने की कोशिश करना जैसी अनेक बातें शामिल हैं। इस समय देश भाजपाईयों द्वारा लोगों का राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रवाद का प्रमाणपत्र बांटे जाने के चलन को लेकर भी बहुत दुरूखी है। ऐसे में देश की नजरें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि क्या 2019 में भी भाजपा की राज्य इकाईयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उसी जोश के साथ आमंत्रित करेंगी जैसाकि 2014 में किया था? क्या 2014 की ही तरह कांग्रेस व नेहरू–गांधी परिवार के विरोध पर आधारित मोदी–शाह का भाषण 2019 में भी उन्हें उर्जा प्रदान करेगा? या फिर तीन बड़े राज्यों में हार की छाया 2019 पर भी पड़ेगी? आने वाला समय देश के साथ–साथ भाजपा की भीतरी राजनीति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा?

– आलेख तनवीर जाफरी

'सोशल मीडिया ने विश्व को जोड़ा, एएमयू की बनाई जा रही गलत छवि'

-आरजे कल्पना

?सोशल मीडिया और टीवी की चकाचौंध के बीच दशकों पुराने मनोरंजन के सहारे रेडियों का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ है। मध्यम और गरीब वर्ग जब दिन भर की थकान के बाद रेडियो ऑन करता है तो यहीं उसके सुकून का साधन होता है। अमीर वर्ग गाड़ी में चलते हुए या फिर सफर के दौरान रेडियो चैनल खोलना नहीं भूलता। केवल टी वी के इस दौर में गांव देहात में आज भी रेडियो मनोरंजन और खबरों का सबसे बडा माध्यम बना हुआ है। शहर के मौहल्ले हो या फिर दूर दूराज के गांव, तमाम सारे लोग रेडियों के विभिन एफएम चैनलों पर आने वाले टेलीफोनिक कार्यक्रमों में घंटो सिर्फ इसलिए फोन लगाते मिल जाएगे कि बस सिर्फ एक मिनट वो रेडियों पर आ सके। देशभर में एफएम चैनलो पर कई चर्चित रेडियों के चेहरे है जिन्हें करोड़ो लोग फॉलो करते है।

अलीगढ़ मे भी रेडियो की अपनी अलग अहमियत है। एफएम चैनल 92.7 बिग एफएम शहर के लोगो के दिलों में अहम जगह बना चुका है। इन दिनों बिग एफएम के आर जे कल्पना शहर वासियों के दिलों में प्रातः प्रसारित होने वाले अपने शो बिग चाय के जरिए चर्चाओ में है। बिग मेहमान कार्यक्रम के जरिए कल्पना शहर की विभिन्न हस्तियो से लोगों को रूबरू कराती रहती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्रा रही आर जे कल्पना की हसती खिलखिलाती आवाज और उसके साथ दिल को छू जाने वाले गाने साल भर में ही शहर का सितारा बना चुके है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है।

व्यवस्था दर्पण से विवेक शर्मा ने आर जे कल्पना से विशेष बातचीत की। पेश है वार्ता के प्रमुख अंशः

व्यवस्था दर्पण : सोशल मीडिया और टीवी के इस दौर में आपने रेडियो को कैरियर के रूप में क्यो चुना?

आरजे कल्पना : रेडियो अपनी बात खुलकर कहने के लिए अच्छा प्लेटफार्म है, पावरफुल मीडिया यही है। अन्य जगहों के मुकाबले लोगों से अपने मन की बात पूर्ण स्वतंत्रता के माध्यम से रेडियो पर ही संभव है। विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोगों से एकसाथ दिल की बात यहा हो जाती है।

व्यवस्था दर्पण : फेक न्यूज का चलन बढ़ रहा है। किस नजरिए से देखती है?

आरजे कल्पना : बिना प्रमाणिकता वाली खबरों को फैलाने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। धर्म व जाति से जुड़ी फर्जी खबरों का चलन रोकने के लिए बिना पढ़े और जाने हमें इन्हें इग्नोर करना होगा। फेक न्यूज जनहित के लिए घातक है।

व्यवस्था दर्पण : सोशल मीडिया समाज में जहर फैला रहा है। आपकी प्रतिक्रिया?

आरजे कल्पना : सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का अच्छा प्लेटफार्म है। दुनिया को एकसाथ जोड़ा है। रेडियों में लिमिटेशन है। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई लिमिट नहीं है। हां, कुछ लोग इसका दुरूपयोग कर समाज में नफरत फैला रहे है, इन्हें रोकना होगा।

व्यवस्था दर्पण : आप एएमयू में पढ़ी है, एएमयू बवाल पर आपकी प्रतिक्रिया?

आरजे कल्पना : मैं एएमयू में पढ़ी हूं, यूनिवर्सिटी की गलत छवि बनाई जा रही है। राजनैतिक फायदे के लिए एएमयू का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। यहां प्रवेश के लिए छात्र तरसते है। बवाल के लिए मैं छात्रनेताओं को जिम्मेदार मानती हूं। दोनों पक्षों को जिम्मेदार बनना होगा। हम जैसे लोगों को चंद लोगों की वजह से यूनिवर्सिटी की बनाई जा रही गलत छवि का सामना करना पड़ता है।

व्यवस्था दर्पण : अलीगढ़ और युवाओं के लिए कोई संदेश?

आरजे कल्पना : हम लकी है कि एएमयू जैसा संस्थान हमारे शहर में है। अभिभावकों, प्रतिनिधियों को यह महत्वता समझनी चाहिए। एएमयू को शिक्षा के लिए व अपने भविष्य संवारने के नजरिए से देखे। एकता और सद्भाव जरूरी है। एएमयू पर किसी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए।

ACN INTERNATIONAL SCHOOL

Developing Global Leaders

ADMISSION OPEN

Nursery To Class VIIIth

Facilities

- Hostel For Girls & Boys
- Transport Facility
- Summer Camp
- Computer Lab
- Language Lab
- Science Lab
- Library
- Sports
- Competitions
- Cultural Programme
- Co-Curricular Activities

Designed & Printed By: The desig 8006310310 8307657849 solution

ACN INTERNATIONAL SCHOOL

ACN Campus, Kasimpur Power Hose Road, Satha Sugar Mill, Aligarh-202127 (U.P.)

Head Office : Grand Plaza, Marris Road, Civil Lines, Aligarh-202002

Website : www.acnis.in, | Email : acnschool@yahoo.in

Contact No.: 9634296781, 7535826273

देशद्रोह !

▸ जियाउर्रहमान

आजादी के सात दशक बाद हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। धर्म और जाति के वर्चस्व वाली राजनीति के इस दौर में देश में हर कोई एक दूसरे को देशभक्त और देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांट रहा है। नेताओं की जमात का आलम यह है कि उनकी बदजुबानी ने देशभर में शहर की गलियों से लेकर गांव देहात तक नफरत और जहर का वो बीज बो दिया है जो शायद ही खत्म हो पाये। सत्ता हथियाने की लड़ाई में राजनेताओं ने वोटबैंक और ध्रुवीकरण के लिए देशहित को ताक पर रखकर धर्म और जाति की ऐसी अफीम बोई है कि जिससे नौजवान हो या बुजुर्ग, महिला या बच्चा, कोई भी अछूता नहीं है। न किसी को देश में शिक्षा व्यवस्था की फिक्र है, न रोजगार की और न ही स्वास्थ्य की। सड़क, पानी, बिजली, मकान, भुखमरी, किसानों की बदहाली की तो बात छोड़िये, जिक्र तक पार्टियों और नेताओं के मुद्दों में नहीं है। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक दूसरे के धर्म को गालियां और एक दूसरे को मिटा देने की चर्चायें हैं। मानो ऐसा लगता है कि देश ने हर मोर्चे पर विकास कर लिया है और अब समस्या सिर्फ हिन्दू और मुस्लिम की रह गई है। नेताओं के बयान आग में घी का काम करते हैं और देश को ध्रुवीकरण और नफरत की आग में झोंक रहे हैं। यूं तो देश में पिछले एक दशक में तमाम ऐसी घटनायें हुई हैं जिन्होंने न सिर्फ मानवता को शर्मशार किया है अपितु देश के प्रत्येक नागरिक को सोचने को मजबूर किया है। इन दिनों देश में देशद्रोह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। जेएनयू से शुरू हुआ देशद्रोह का खेल अब एएमयू तक पहुंच चुका है। पुलिस और प्रशासन ने कानून का चीरहरण ऐसा कर दिया है कि बिना तथ्यों और जांच पड़ताल किये सत्ता के इशारे पर देशद्रोह लगा दी जाती है। हां, इतना जरूर है कि आजाद भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने वाले और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे जिसे भारत के कानून ने फांसी की सजा दी थी, जिंदाबाद कहने वालों की मौज बहार है। न उनके लिए देशद्रोह है, न ही सख्त कानून। बापू के इस देश में बापू की इतनी दुर्गति कभी हुई हो जितनी कि अब हो रही है। देशद्रोह सात दशक बाद राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया का आलम तो यह है कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को देशद्रोही साबित करने का चलन बन चुका है। धर्म और जाति के प्रभाव वाली राजनीति में विचारणीय प्रश्न यही है कि छात्र गुटों के आपसी विवाद में देशद्रोह का कानून छात्रों पर लगेगा या फिर आजादी के महानायक महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा? सत्ता के बल पर फिलहाल पुलिस और प्रशासन जिस तरह से चाहे धाराओं का खेल कर पल्ला झाड़ ले लेकिन इतिहास कभी किसी को

अलीगढ़ के माथे पर लगा राष्ट्रपिता गांधी के पुतले को गोली मारने का कलंक

शिक्षा और तहजीब के लिए दुनियाभर में विख्यात अलीगढ़ के अध्याय में 30 जनवरी, बुधवार का दिन काले अक्षरों में लिख गया। अलीगढ़ में घटित हुई राष्ट्रपिता के पुतले को गोली मारने की घटना ने देश ही नहीं, विश्व में अलीगढ़ को कलंकित कर दिया। दुनिया भर में अहिंसा के पुजारी माने जाने वाले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव हिंदूवादी नेता पूजा शकुन पांडेय ने न सिर्फ गांधी के हत्यारे गोडसे का गुणगान किया बल्कि राष्ट्रपिता के पुतले को गोलियां भी मारी। गोलियां मारकर आजादी के महानायक रहे महात्मा गांधी के पुतले को जलाया भी गया और उन पर अभद्र टिप्पणियां की गई। इतना ही नहीं, राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महात्मा बताकर उसका गुणगान किया गया और अमर रहने के नारे भी लगाये गये। आजाद हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारकर जलाने की इस घटना ने अलीगढ़ सहित देश के आम जन और सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी। आनन फानन में अलीगढ़ पुलिस ने थाना पूर्ति के लिए गांधी पार्क थाने के एसआई संजीव कुमार की तहरीर पर इस मामले में पूजा शकुन पांडेय, उनके पति अशोक कुमार पांडेय, मनोज, राजीव, जयवीर शर्मा, अभिषेक, गजेंद्र कुमार, अनिल वर्मा, महिला कार्यकर्ता उत्तमा सिंह व एक अज्ञात सहित कुल दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। देशभर में हल्ला मचने के बाद पूजा शकुन पांडेय को पति सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन घटना ने देश में कई सवाल खड़े कर दिये है।

30 जनवरी को अखिल भारत हिन्दू महासभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान शहर के बी दास कंपाउंड में महात्मा गांधी के पुतले को राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय ने पहले तीन गोली मारी और फिर पुतला दहन किया। महात्मा गांधी मुर्दाबाद और महात्मा नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पूजा शकुन पांडेय का गांधी के पुतले को गोली मारने का वीडियो देशभर में वायरल हो गया और पक्ष और विपक्ष में बहस होने लगी। अधिकतर लोगों ने योगीराज में हुई इस घटना की निंदा की और इसे गांधी की विचारधारा का कत्ल करार दिया।

जेल से रिहा होने के बाद भी करती रही गोडसे का गुणगान

राष्ट्रपिता गांधी के पुतले को गोली मारकर हत्यारे गोडसे को अमर कहने वाली हिंदुवादी नेता पूजा शकुन पांडेय जेल से रिहा होने के बाद भी गांधी के हत्यारे गोडसे का गुणगान करती रही।

पूजा शकुन ने सवाल किया कि देश मुझे बताएं और जो मेरी आलोचना करते हैं वह मुझे बताएं बॉर्डर पर गांधी के चरखे की जरूरत है या फिर गोडसे की पिस्तौल की...!!

राम मंदिर पर का शांति और क्रांति से श्री राम मंदिर बने मेरी जिस दिन रिहाई हुई उसी दिन पुलवामा में आतंकवादियों ने ऐसा घिनौना कृत्य किया... ना आंसू निकल रहे हैं ना समझ में आ रहा कितनी क्षति हुई है देश की, ऐसे में आप लोगों से पूछती हूं आज के दिन की स्थिति में गांधी जी की आवश्यकता है या फिर गोडसे की, 1947 की गलती की वजह से आज हमारे जवान शहीद हुए है, आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा इस भीभत्स कांड का, आज लोगों को 40 की जगह 400 सिर चाहिए, आज जो काम देश चाहता है वही काम उस समय गोडसे ने किया था, मैं अपने प्रधानमंत्री से खुला आव्हान करती हूं और पत्र लिखकर मांग करती हूं कि मैं किसी भी तरह से तैयार हूं... चाहे आप मुझे मानव

"गांधी के पुतले को गोली मारना और उनके हत्यारे का जय-जयकार करना बेहद शर्मनाक है। भाजपा के राज में ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोषियों पर देशद्रोह की कार्यवाही होनी चाहिए थी लेकिन प्रशासन ने सत्ता के दबाव में धाराओं में खोल कर दिया। पुतुमयू के छात्रों पर देशद्रोह लगाना निंदनीय है।"

–तिलकराज बाबर, जिलाध्यक्ष अलीगढ़ बसपा

JEEVAN JYOTI INSTITUTE

B.A.M.S.

D. Pharma

B.Sc Nursing

O.T. Technician

G.N.M.

Physiotherapy

A.N.M.

Optometry

खैर रोड, लोधा, अलीगढ़

सम्पर्क : 9927066368, 8755018000, 9927742600, 9837086858

बम बना कर भेज दीजिये में तैयार हूं, महात्मा गांधी से नफरत के बारे में बोला की वो मात्रभूमि का हत्यारा है,,,मैंने हमेशा ही उनका विरोध किया है और करती रहूंगी, जीरो टोरेलेंस, बात करते हुए भावुक गौड़से लेडी, हर समय गांधी विचारों को गलत बताती रही ,,,,!!

एएमयू छात्रसंघ ने कराया बखेड़ा

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति ने देश और दुनिया ने कई अच्छे नेता दिये है और देशभर में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन वर्तमान में एएमयू की छात्र राजनीति गुटबाजी और कौमपरस्ती के नाम पर कैम्पस तक सिमट कर रह गई है। छात्र कल्याण और छात्र हित के मुद्दे छोड़ एएमयू छात्रसंघ ने महागठबंधन के ऐलान के बाद मुस्लिम पार्टियों को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए कैम्पस में मुस्लिम फ्रंट बनाने का ऐलान किया और जिन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम है, को 12 फरवरी के लिए आमत्रिंत कर दिया। एआईएमआईएम के मुखिया असदउद्दीन औवेसी को भी छात्र संघ ने न्यौता भेज दिया। कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद, आरजेडी जैसी पार्टियों जिन्हें कि मुस्लिम समाज का बड़ा तबका वोट देता आ रहा है, को छेक दिया। छात्रसंघ के औवेसी को बुलाने के न्यौते के बाद एएमयू के चर्चित छात्र नेता ठाकुर अजय सिंह ने सवाल उठाने खड़े कर दिये और मुस्लिम फ्रंट बनाने के कार्यक्रम को छात्र कल्याण के रूपये की बर्बादी करार दिया। अजय सिंह के साथ एएमयू के पूर्व छात्र और भाजपा के मीडिया प्रभारी निशित शर्मा ने भी असदउद्दीन औवेसी को बुलाने का विरोध कर कार्यक्रम का बहिस्कार करने की चेतावनी दे डाली। एएमयू छात्र संघ के छात्र हितों के मुद्दों को छोड़ कथित कौमपरस्ती के इस कार्यक्रम के मीडिया ट्रायल और छात्र नेताओं की अपरिपक्वता ने बखेड़ा करा दिया और एएमयू विरोधियों को सवाल उठाने का मौका दे दिया।

अजय से मारपीट, मीडिया से अभद्रता और भाजपाईयों की मौजदूगी से हुआ बवाल

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवसिर्टी यू ंतो अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर लाइमलाइट में रहती है लेकिन इस बार अमुवि छात्र नेताओं की अपरिपक्वता ने फजीता करा दिया। मुस्लिम फ्रंट

" एएमयू छात्रों पर आरएसएस और बीजेपी के दबाब में झूठी देशद्रोह की धारा लगाई थी, एएमयू में भाजपा और आरएसएस की दखलअंदाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी। नाथूराम गोडसे के पुजारियों पर देशद्रोह लगाना चाहिए था लेकिन पुलिस ने ऐसा नही किया। देशद्रोह बीजेपी के इशारे पर निर्दोष व बेगुनाह लोगों पर लगाया जा रहा है। "

-हुजैफा आमिर, सचिव एएमयू छात्र संघ

के कार्यक्रम में औवेसी का आगमन का विरोध करने पहुचे अमुवि के छात्र नेता ठाकुर अजय सिंह से धक्का मुक्की और मारपीट की गई। अजय सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराने पहुचे थे जो कि लोकतांत्रिक रूप से उन्हें अधिकार भी था। लेकिन अराजक तत्वों ने अजय से अभद्रता और धक्का मुक्की शुरू कर दी । पुलिस की मौजूदगी में ही टकराव होते होते बचा। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी और निशित शर्मा को जैसे ही अजय से मारपीट की सूचना मिली तो वह भी यूनिवर्सिटी सर्किल जा पहुचे। भाजपाईयों को देखते ही अमुवि छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया और दोनो ओर से जमकर मारपीट हुई। पुलिस चाहती तो भाजपा नेताओं को सर्किल तक आने से रोक कर टकराव टाल सकती थी लेकिन लेकिन एक बार फिर पुलिस की लापरवाही से शहर में तनाव और फजीहत हो गई। दोनों पक्षों ने तो मारपीट और बवाल के दौरान एक दूसरे पर फायरिंग करने तक का आरोप लगाया है। वहीं हाल ही में शुरू हुए एक टीवी चैनल की महिला रिपोर्टर से भी उसी दिन अभद्रता और मारपीट की गई । जिसने भी एएमयू की राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत कराई। अजय और मीडियाकर्मियों से मारपीट न होती तो शायद यह बवाल भी न हा. ता।

सत्ता की हनक से एएमयू छात्रों पर लगा देशद्रोह!

अमुवि सर्किल पर छात्र नेता ठाकुर अजय सिंह और

'' देशद्रोह को भाजपा के इशारे पर देशभर में पुलिस ने तमाशा बनाकर रख दिया है। गांधी के हत्यारों को बढ़ावा देने वालों को मामूली धाराओं में जेल भेजा जाता है जिन पर देशद्रोह का मुकद्मा दर्ज होना चाहिए था। देशद्रोह का उपयोग अब धर्म विशेष को देखकर होने लगा है। ''

– चौधरी बिजेन्द्र सिंह, पूर्व सांसद, कांग्रेस

भाजपाईयों से मारपीट के बाद लड़ाई भाजपा बनाम अमुवि छात्र हो गई। सत्ता से जुड़ा मामला होने के चलते देशभर की सुर्खियों में एक बार फिर एएमयू आ गया। भाजपा नेताओं को पीटने की खबरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी वहीं एएमयू की तरफ से भी तमाम तरह के पोस्ट वायरल होने लगे। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर हजारों छात्रों ने डेरा डालकर धरना लगा दिया। कैम्पस छावनी में तब्दील हो गया। एएमयू छात्रों पर भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह की ओर से मुकद्मा दर्ज कराया गया, जिसमें नदीम अंसारी, जैद शेरवानी, छात्रसंघ सचिव हुजैफा आमिर, उपाध्यक्ष हमला सूफियान, मो.आमिर, नवेद आलम, छात्रसंघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज, पूर्व अध्यक्ष मशकूर अहमद, आरिफ त्यागी, फरहान जुबैरी, नजमुल साकिब, जकी, रिहान, असद व अन्य अज्ञात एएमयू छात्र आरोपी बनाए गए । तहरीर में आरोप है कि मुकेश सिंह अपने साथी मनोज शर्मा संग किसी काम से कलेक्ट्रेट जा रहे थे। तभी एएमयू सर्किल पर हमलावर एएमयू छात्रों ने उनकी गाड़ी को देखकर हमला बोल दिया। गाड़ी से उन्हें व मनोज को खींचकर पीटा। फायरिंग की। इस फायरिंग में मुकेश बच गए। गोली उनकी गाड़ी में लगी। वहीं मनोज से मोबाइल जंजीर आदि लूटकर बेरहमी से पीटा गया। बाद में देश विरोधी व भाजपा और पीएम विरोधी नारेबाजी करते हुए हमलावर भाग गए। किसी तरह मुकेश वहां से बचकर भागे। भाजपा नेताओं की पिटाई से भाजपा फ्रंटफुट पर आ गई और मामला सीएम दरबार तक पहुच गया। पुलिस ने छात्रों पर देशद्रोह की धारा भी

बढ़ा दी। देशद्रोह लगाने से गुस्साये छात्रों ने धरना बड़ा कर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। देशद्रोह की धारा लगाने की गूंज सियासी गलियारों तक पहुच गयी और मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। क्योंकि देशविरोधी नारे लगाने की बात सिर्फ कथित रूप से थी कोई साक्ष्य नहीं था इसलिए पुलिस ने सियासी दबाब और देशभर में हुइ किरकिरी के बाद देशद्रोह की धारा हटा दी। पुलिस की कार्यवाही के बाद देशद्रोह को लेकर नई बहस छिड़ गई है। गांधी के पुतले को गोली मारने वालों पर रहम और छात्र गुटों में आपसी विवाद के चलते अमुवि छात्रों पर देशद्रोह का सितम चर्चा का विषय बना हुआ है।

मुस्लिम प्रेम हुआ काफूर, नहीं आयें औवेसी

एएमयू में हुआ बवाल मुस्लिम सियासत से शुरू हुआ था लेकिन पुलिसिया कार्यवाही के खिलाफ और छात्रों के समर्थन में एक भी कथित मुस्लिम पार्टी समर्थन में नहीं आई। एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदउद्दीन औवेसी के आगमन को लेकर विरोध शुरू हुआ था लेकिन अमुवि छात्रसंघ के नेताओं का मुस्लिम प्रेम उस वक्त काफूर हो गया जब भा. जपाईयों के साथ टकराव और देशद्रोह का मुकद्मा दर्ज होने के बावजूद औवेसी ने एएमयू के समर्थन में एक बयान तक देना उचित नहीं समझा। अमुवि छात्रसंघ के नेताओं ने दर्जनभर पार्टियों को मुस्लिम पार्टिया बताते हुए मुस्लिम फ्रंट की बैठक में आमंत्रित किया था लेकिन बवाल में छात्रों के समर्थन में एक भी पार्टी धरने में दिखाई नहीं दी। हां इतना जरूर रहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं ने बवाल के बाद छात्रों के समर्थन में पहुचकर न सिर्फ उनकी आवाज उठाई बल्कि प्रशासन पर भी दबाब बनाया। अमुवि छात्रसंघ मुस्लिम फ्रंट बनाने के कार्यक्रम और बाद में हुए बवाल के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों में छात्र नेताओं के खिलाफ आक्रोश है।

यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही से सर सैयद की बगिया हो रही बदनाम

सर सैयद अहमद खान ने जिस उद्देश्य से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की , इस दौर में आकर उस मिशन को यूनिवर्सिटी प्रशासन ही धब्बा लगा रहा है। कभी तिरंगा यात्रा

निकालने पर छात्रों को नोटिस देकर देशभर की सुर्खियों में कैम्पस को ले आता है तो कभी जिन्ना की तस्वीर प्रकरण में मौन साध लेता है। हाल ही में अमुवि छात्रसंघ के मुस्लिम फ्रंट बनाने के कार्यक्रम से विश्वविद्यालय में कई दिन तक बवाल हुआ। वह सब भी इंतजामिया की लापरवाही का ही एक नतीजा है। विवि प्रशासन को छात्र कल्याण के पैसे से धार्मिक और सियासी कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी और यदि अनुमति नहीं ली गई थी तो भी छात्रसंघ नेताओं पर कार्यवाही करनी चाहिए थी। लेकिन इंतजामिया है कि आंख और कान बंद किए रहता है लेकिन जब हंगामा बढ़ता है तो नोटिस और चुनिंदा छात्रों पर नाममात्र कार्यवाही कर पल्ला झाड़ लेता है। लोगों का सवाल यही है कि आखिर क्यों विवि प्रशासन हर बार सर सैयद की बगिया पर सवाल उठाने के मौके देता है?

मैं एएमयू का स्टूडेंट्स था मेरे हिस्से में सिर्फ धोखा आया...

अमुवि छात्रसंघ के नेताओं ने मुस्लिम फ्रंट की बैठक के बाद उपजे विवाद में जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी। अखबारबाजी हुई, मीडिया ट्रायल हुआ लेकिन एक भी नेता को जेल भेजने की हिम्मत पुलिस नहीं दिखा सकी। अमुवि के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र तालिब को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सीसीटीवी फुटेज में होने का हवाला देते हुए धारा 147, 149, 153ए, 379, 201, 427, 435 में जेल भेज दिया। एएमयू छात्रसंघ के नामजद नेताओं की जगह अज्ञात में तालिब को जेल भेजने से छात्रों में आक्रोश देखा गया। दरअसल भाजपा नेता डॉ निशित शर्मा ने अमुवि के फर्रुख लोधी, नदीम अंसारी, हुजैफा आमिर, सद्दाम हुसैन, फिरोज आलम / राजा , रेहान सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तालिब की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमे तालिब को आम छात्र बताते हुए उसके साथ धोखे की बात कही जा रही है । अलीगढ़ में यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

'' देशद्रोह का राजनैतिक दुरूपयोग बंद होना चाहिए, गांधी के पुतले को गोली मारकर कुछ लोगों ने पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुचायी, सीधे-सीधे संविधान में दिए गये मूल कर्तव्यों पर प्रहार किया गया।सरकार और पुलिस को देशद्रोह में मुकद्मा दर्ज करना चाहिए था। ''

- एड0 फूलसिंह बघेल

शारिक ठाकुर नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा है कि "किसी की राजनीति चमकी तो किसी के हिस्से में प्रमोशन आया, मै एएमयू का आम स्टूडेंट्स था, मेरे हिस्से में सिर्फ धोखा आया"। फेसबुक पर वायरल हो रहे पोस्ट में अमुवि छात्र संघ के नेताओं पर उंगली उठाई गई है । कैंपस में अंदरूनी गुटों की राजनीति हावी है। माना जा रहा है कि तालिब उसी गुटबाजी का शिकार हुआ है ।

जनवरी जाते जाते और फरवरी के प्रारम्भ में ही गांधी के पुतले को गोली मारने और एएमयू में औवेसी के कार्यक्रम ने अलीगढ़ को देशभर की सुर्खियों में रखा। हालांकि अमुवि का बवाल अब शांत हो चुका है। लेकिन फिजाओं में अभी भी छात्र गुटों के विवाद में पुलिस द्वारा देशद्रोह लगाना और फिर हटाना गूंज रहा है। वहीं महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का गुणगान कर राष्ट्रपिता के पुतले को गोली मारने वालों का हल्की धाराओं में चालान कर जेल भेजना और देशद्रोह की धारा न लगाना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यहीं है कि आखिर 'देशद्रोह ' को पुलिस ने सियासी हथियार क्यों बना लिया है?

–लेखक व्यवस्था दर्पण के संपादक है।

छात्रहित छोड़ धार्मिक एजण्डे को आगे बढ़ा रहा एएमयू छात्रसंघ

-ठाकुर अजय सिंह

संघ अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन छात्रो के बीच हुए हिंदु मुस्लिम ध्रुवीकरण के चलते अजय सिंह हार गए और उन्हें करीब 2500 वोट प्राप्त हुए। भाजपा के विधायक ठाकुर दलवीर सिंह के पौत्र अजय सिंह गत माह कैम्पस में तिरंगा यात्रा निक. ालकर तब चर्चाओं में आये जब विवि प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकालने पर उन्हें नोटिस थमा दिया। तिरंगा यात्रा का प्रकरण अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अजय सिंह ने छात्र कल्याण के पैसे का दुरूपयोग रोकने के लिए औवेसी के कार्यक्रम का विरोध कर दिया। अजय सिंह एएमयू से चुनाव भले ही न जीत पाये हो लेकिन छात्रों की आवाज बुलंद करने और विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रहने के चलते सुर्खियों में है। व्यवस्था दर्पण ने एएमयू की छात्र राजनीति पर उनसे वार्ता की। पेश है बा. तचीत के प्रमुख अंशः–

व्यवस्था दर्पण : औवेसी के आगमन का आपने विरोध किया और फिर बवाल हुआ। विरोध का कारण?

अजय सिंह : छात्रसंघ छात्रों के रूपये से बनता है, छात्र हितों के लिए बनता है, छात्रों की समस्या उठाना, उनकी आवाज बुलंद करना छात्रसंघ की प्राथमिकता में होना चाहिए लेकिन वर्तमान एएमयू छात्रसंघ मुस्लिम फ्रंट बनाकर उसमें आ. ेवेसी को बुलाकर छात्रों के रूपये की बर्बादी कर रहा था। इसलिए विरोध किया गया। छात्रों के रूपये पर छात्रों का हक है। छात्रों के रूपये पर राजनीति नहीं होने दी जाएगी। धार्मिक एजण्डे को छोड़ यूनियन किसी स्कॉलर को बुलाती, छात्रों को रोजगार के अवसर के लिए कैम्प लगवाती तो कोई विरोध नहीं किया जाता।

व्यवस्था दर्पण : अमुवि छात्रसंघ के छात्रहितो से भटकने के क्या कारण मानते है?

अजय सिंह : छात्र संघ की मौजूदा यूनियन खुद की नेतागिरी चमकाने के लिए छात्रहितों को भूल धार्मिक एजेण्डा बढ़ा रही है। मुस्लिम फ्रंट बनाना और औवेसी को बुलाना उसी का एक उदाहरण है। छात्र नेता शेरवानी की मान–मर्यादा भूल पार्टियों की चापलूसी करने को प्राथमिकता दे रहे है। छात्रों के मुद्दे उनकी प्राथमिकता में नहीं है। जिसका एक बड़ा कारण छात्रनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है।

व्यवस्था दर्पण : मुस्लिम फ्रंट बनाने के छात्रसंघ के दावे को किस नजरिए से देखते है?

अजय सिंह : एएमयू छात्रसंघ का अपना एक गरिमामयी इतिहास है। लेकिन इस यूनियन के सचिव के पिता कथित मुस्लिम हितैषी पार्टी के अध्यक्ष है। जब उन्हें किसी पार्टी ने तवज्जों नहीं दी तो उन्हीं के एजण्डे को आगे बढ़ाने के लिए फ्रंट बनाने का ऐलान किया। छात्र संघ को धर्म और जाति की राजनीति से दूर रहना चाहिए। लेकिन अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए यूनियन विवि को बदनाम करवा रही है।

व्यवस्था दर्पण : आप पर आरएसएस का एजेण्डा अमुवि में बढ़ाने का आरोप लगता है?

अजय सिंह : एएमयू के मठाधीशों ने छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाने के कारण मेरी छवि मुस्लिम का दुश्मन होने की तरह पेश की है। मैंने हमेशा सर सैयद अहमद खान की बगिया के प्रत्येक फूल के हित की बात की है, उनके मुद्दे उठाये है। बस यहीं मठाधीशों को खलता है इसलिए वह तमाम तरह की अफवाहें उड़ाते है। कैम्पस में धर्म और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लोग मुस्लिमों के भी हितैषी नहीं है। मुस्लिमों को गुमराह कर उनके नाम से राजनीतिक रोटियां सेकते है। विवि में गरीब, पिछड़े मुसलमान को जगह ही नहीं है, यूनियन से लेकर प्रशासन तक भाई भतीजावाद , परिवारवाद बढ़ाने में लगा है। इसी सवाल को उठाने पर मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है ताकि धर्म विशेष के छात्रों को बरगलाया जा सके।

व्यवस्था दर्पण : अमुवि छात्रसंघ का रूतबा कम हुआ है, ऐसा क्यों?

अजय सिंह : छात्र संघ वर्तमान में छात्रों के मुद्दें, देशभर में छात्रों की समस्याओं पर बोलने की बजाय धार्मिक एजण्डे बढ़ाने पर लगा है। छात्रों के कल्याण से अब छात्रसंघ के नेता दूर भागते है। यही कारण है कि छात्रसंघ को अब छात्र भी उतना महत्व नहीं दे रहे। छात्र संघ के नेता अब विभिन्न पार्टियों को खुश क रने और उनका एजेंट बनकर रहने से ही संतुष्ट है। अब सरकार से सवाल करने तक की हिम्मत वह नहीं करते। इसीलिए छात्रसंघ का रूतबा कम हुआ है।

ठाकुर अजय सिंह से इसके अतिरिक्त कई बिंदुओं पर चर्चा हुई जिस पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। उनसे वार्ता कर यह तो स्पष्ट हो गया कि उनकी लड़ाई धर्म आधारित न होकर छात्र आधारित रही है जिसे छात्रसंघ के मठाधीश नहीं पचा पा रहे है।

योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतार कर भाजपा ने चली है दोहरी चाल

सब जानते हैं कि मायावती बहुत सोच-समझकर ही सियासी चाल चलती हैं, उनकी राजनीतिक समझ अच्छी है। एक तो बंगाल में मायावती या फिर उनकी बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी नहीं है, इसलिए वह उदासीन बनी हुई हैं दूसरे वह ममता को समर्थन देकर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी दावेदारी को मजबूती नहीं प्रदान करना चाहती हैं।

▸ अजय कुमार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया है। ममता जब कोलकाता में धरने पर बैठीं तो उसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई दी। ममता के धरने वाले पंच में उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज फंसे नजर आ रहे हैं। यूपी के चार बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ममता की सियासत का मोहरा बन गये। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और अमेठी के सांसद राहुल गांधी भी ममता की सियासत के सामने बैकफुट पर नजर आए। एक तरफ ममता ने धरने के माध्यम से भाजपा के तमाम नेताओं को आईना दिखाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ धरने के माध्यम से वह अपनी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी मजबूत करती नजर आईं।

ममता ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की तो यूपी से सांसद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं कांग्रेस अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार समझे जा रहे राहुल गांधी और गैर भाजपा, गैर कांग्रेस के सहारे प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए अपनी पकड़ मजबूत करने में लगीं बसपा सुप्रीमो मायावती को ममता की यह बात रास नहीं आई। सबने अपने–अपने ढंग से रिएक्शन दिया।

खैर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से ममता की अदावत जगजाहिर है। मोदी के सहारे भाजपा बंगाल में हिन्दुत्व की अलख जगाए हुए है। इसीलिए ममता दीदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के किसी भी नेता का बंगाल आना पसंद नहीं आता है। ममता पीएम मोदी से क्यों परेशान थीं। इस बात का अहसास तब हुआ जब मोदी की रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मोदी की तरह ही अमित शाह भी बहुत मुश्किल से बंगाल में घुस पाए थे। हिन्दुत्व का चेहरा समझे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिये भी ममता दीदी ने हवा–पानी और सड़क सभी जगह अवरोध खड़े किए। इसको लेकर योगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर भी रहे। बंगाल में घुसने नहीं दिए जाने के कारण योगी को एक जनसभा तो टेलीफोन से संबोधित करनी पड़ गई। हाँ, यह और बात थी कि योगी ने हार नहीं मानी। भारी दबाव के बीच टीएमसी नेताओं को चकमा देते हुए वह पुरूलिया में एक जनसभा करने पहुंच ही गए। जहां उन्होंने ममता को खूब खरी–खरी सुनाई।

उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ ममता दीदी का रवैया प्रदेश के लोगों को रास नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता में ममता के प्रति जबर्दस्त नाराजगी है। योगी के अपमान को यूपी का अपमान बताया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इन सब बातों से बेपरवाह होकर ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए

भाजपा पर ही हमलावर हैं। अखिलेश जो स्वयं खनन घोटाले सहित कई भ्रष्टाचार के चलते सीबीआई के रडार पर हैं, उन्हें यही लगता है कि केन्द्र की मोदी सरकार विरोधियों को डराने के लिये सीबीआई और ईडी का सहारा ले रही है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले में एसआईटी जांच के प्रमुख रहे राजीव कुमार से सीबीआई की पूछताछ की कोशिशों को लेकर कोलकाता में राजनीति जोरों पर है। पहले जांच को पहुंचे सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में लिया गया और फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही धरने पर बैठ गईं। जब ममता धरने पर बैठीं तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाल रहे राजीव कुमार भी उन्हीं के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपने सर्विस रूल्स की जरा भी चिंता नहीं की। ममता का धरना कई सवाल खड़ा कर रहा था, लेकिन इन सब बातों की चिंता छोड़कर समूचा विपक्ष ममता के साथ खड़ा दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आन्ध्र प्रदेश के सीएम चन्द्रबाबू नायडू और राजद नेता तेजस्वी व भाजपा के बागी नेता भी ममता के समर्थन में हुंकार भरते रहे, लेकिन ममता दीदी के समर्थन में बहन मायावती जी का कहीं नहीं दिखना रहस्यमय बना हुआ है।खबर चली कि ममता बनर्जी के धरने को मायावती ने फोन करके समर्थन दिया था, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। मायावती खुले तौर पर ममता के समर्थन में नहीं दिखती हैं। मायावती की चुप्पी के चलते अखिलेश कुछ असहज भी नजर आ रहे हैं, लेकिन राजनैतिक रूप से अनुभव के मामले में अखिलेश, बसपा सुप्रीमो के आसपास भी नजर नहीं आते हैं। सब जानते हैं कि मायावती बहुत सोच–समझकर ही सियासी चाल चलती हैं, उनकी राजनीतिक समझ अच्छी है। एक तो बंगाल में मायावती या फिर उनकी बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी नहीं है, इसलिए वह उदासीन बनी हुई हैं दूसरे वह ममता को समर्थन देकर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी दावेदारी को मजबूती नहीं प्रदान करना चाहती हैं। इसके अलावा मायावती भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी नहीं दिखना चाहती हैं। भले ही उनकी सरकार के समय हुए स्मारक घोटाले की जांच चल रही हो। कभी–कभी तो ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद के गणित को ध्यान में रखकर मायावती भाजपा के प्रति अभी नरम रवैया अख्तियार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश से ही आने वाले एक और बड़े नेता राहुल गांधी भी ममता की गुगली को समझ नहीं पा रहे हैं। हालात यह है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी नेता शारदा चिटफंड घोटाले में ममता के खिलाफ सीबीआई की सख्ती को सही ठहरा रहे हैं, वहीं कांग्रेस की केन्द्रीय इकाई एक तरफ सीबीआई की कार्रवाई के बहाने ममता का समर्थन करते हुए मोदी को घेरने में लगी है। दूसरी तरफ उसके नेता यह भी कह रहे हैं कि शारदा चिटफंड घोटाले की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी ममता की प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी रास नहीं आ रही है।

बात भाजपा की कि जाये तो सपा–बसपा गठबंधन के बाद पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होते दिखे रहा है, जिसकी भरपाई भाजपा पश्चिम बंगाल से करना चाहती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में भाजपा को मजबूत करने की जिम्मेदारी मोदी–शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ के भी कंधों पर डाली गई है। भाजपा की कोशिशों से कुछ हद तक बंगाल में हिंदू पोलराइज भी हुए हैं। भाजपा आलाकमान का मानना है कि अगर हिंदू पोलराइजेशन होता है तो पार्टी को पश्चिम बंगाल में 42 में से 25 सीटें मिल सकती हैं, अन्यथा बंगाल अभी दूर है।

2019 की चुनावी बिसात पर राहुल की व्यूह रचना

यूपी में एक तरफ मायावती को लेकर मुस्लिम समेत जाटव छोड बाकि दलित जातियो में ये सवाल अब भी है कि क्या चुनाव के बाद मायावती सत्ता के लिये कही बीजेपी के साथ तो खडा नहीं हो जायेगी । तो दूसरी तरफ अखिलेश के सामने यादव वोट बैक के अलावे ओबीसी जातियो के बिखराव का संकट भी है और मायावती के साथ गठबंधन के बावजूद दलित वोट का ट्रांसंभर ना होने की स्थिति भी है ।

▸ पूण्य प्रसून वाजपेयी

2019 की दौड में नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी अगुवाई कर रहे है तो अगुवाई करते नेता के पीछे खडे क्षत्रप की एक लंबी फौज है जो अपने अपने दायरे में खुद की राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे को बढा रहे है । इस कडी में ममता , मायावती , अखिलेश , चन्द्रबाबू, चन्द्रशेखर राव, कुमारस्वामी ,तेजस्वी , हेमतं सोरेन ,नवीन पटनायक सरीखे क्षत्रप है । लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जा रही है कि राजनीतिक बिसात बनेगी कैसी ।ध्यान दे तो नरेन्द्र मोदी की थ्योरी राष्ट्रवाद को लेकर रही है । इसलिये वह चार मुद्दो को उटा रहे है ।

पहला विदेशो में मोदी की वजह से भारत का डंका बज रहा है । दूसरा, डोकलाम में चीन को पहली बार मोदी की कूटनीति ने ही आईना दिखा दिया । तीसरा , सर्जिकल स्ट्राइक के जरीये पाकिस्तान धूल चटा दी । और चौथा हिन्दुत्व के रास्ते सत्ता चल रही है । और इसके लिये वह नार्थइस्ट में बांग्लादेशियो को खदेडने के लिये कानून बनाने से भी नहीं चूक रही है । लेकिन राहुल गांधी की थ्योरी खुद को राष्ट्रवादी बताते हुये अब मोदी के राष्ट्रवाद की थ्योरी तले इक्नामी के अंधेरे को उभार रही है । राहुल गांधी का कहना है राष्ट्रवादी तो हम भी है । और जहा तक हिन्दुत्व की बात है तो जनेउधारी तो हम भी है । लेकिन दुनिया भर में डंका पिटने के बावजूद मोदी का राष्ट्रवादी गरीबो के लिये कुछ नही कर रहा है ये सिर्फ कारपोरेट हित साध रहा है । यानी 2019 की तरफ बढते कदम मोदी की व्यूह रचना में राहुल की सेंध को ही इस तरह जगह दे रहे है जैसे एक वक्त की काग्रेस की चादर अब बीजेपी ने ओढ ली है और गरीब गुरबो का जिक्र कर काग्रेस में समाजवादी–वामपंथी सोच विकसित हो गई है । यानी 2019 की बनती तस्वीर में क्षत्रपो के सामने संकट पाररंपरिक जाति और धर्म के मुद्दे के हाशिये पर जाने से उभर रहा है । यानी आर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह काग्रेस सक्रिय हो चली है और राममंदिर को जिस तरह मोदी के साथ संघ परिवार ने भी चुनाव तक टाल दिया है उसमें जातिय

समीकरण के आधार पर राजनीति करने वाले क्षत्रपो के सामने ये संकट है कि उनका वोट बैक भी उस विकास को खोज रहा है जो उनके पेट और परिवार से जा जुडा है । इससे क्षत्रपो की सौदेबाजी भी खासी कमजोर हो चली है । यानी इस तस्वीर का पहला पाठ तो यही है बीजेपी क्षत्रपो को जीने नहीं देगी और काग्रेस क्षत्रपो को अपनी शर्तो पर समझौता कराने की दिशा में ले जायेगी । राहुल प्रियका की जोडी काग्रेस में आक्सीजन भर रही है या फिर क्षत्रपो के सामने जीवन मरन का संकट खडा कर रही है । ये सवाल धीरे धीरे इसलिये बडा होता जा रहा है क्योकि काग्रेस के कदम एकला चलो या फिर लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटो पर चुनाव लडकर अपनी संख्या को बढाने के फार्मूले की तरफ बढ चुके है । और ये सब कैसे हो रहा है ये देखना बेहद दिलचस्प है । क्योकि राहुल और प्रियंका एक साथ जब चुनाव प्रचार के लिये उतरेगें तो इसका मतलब साफ है कि यूपी बिहार झारखंड बंगाल, आध्र प्रदेश और उडीसा को लेकर साफ थेयोरी होगी कि क्षत्रपो को राज्यो में अगुवाई की बात कहकर लो. कसभाचतुनाव में ज्यादा से द्यादा सीट खुद लडे । और मोदी विरोध की थ्योरी के सामानातंर पं बंगाल, आध्रप्रेदश और उडिसा में किसी भी क्षत्रप के साथ समझौता ना करें । इस थ्योरी को सिलसिलेवार समझे । यूपी में एक तरफ मायावती को लेकर मुस्लिम समेत जाटव छोड बाकि दलित जातियो में ये सवाल अब भी है कि क्या चुनाव के बाद मायावती सत्ता के लिये कही बीजेपी के साथ तो खडा नहीं हो जायेगी । तो दूसरी तरफ अखिलेश के सामने यादव वोट बैक के अलावे ओबीसी जातियो के बिखराव का संकट भी है और मायावती के साथ गठबंधन के बावजूद दलित वोट का ट्रासंभर ना होने की स्थिति भी है । फिर काग्रेस को लाभ सीधा है । पहला, –काग्रेस आर्थिक आधार पर अपने पारंपरिक वोट बैक को जोडने उतरेगी । तो दूसरा ,महिला, युवा और अगडी जातियो के वोट को प्रियंका के आसरे जोडेगी । तो यूपी से सटे बिहार झरखंड में काग्रेस अपनी सौदेबाजी के दायरे को बढा रही है ।इसलिये बिहार में तेजस्वी हो या झरखंड में सोरेन । दोनो के सामने काग्रेस का प्रस्ताव साफ है , –तेजस्वी–सोरन सीएम बने लेकिन लोकसभा की सीट ज्यादा काग्रेस के पास होगी । और ज्यादा सीटो पर चुनाव लडने का फार्मूला ही पं बंगाल और आध्रपर्देश में काग्रेस को गटबंधन के बोझ से मुक्त कर चुका है । उसलिये काग्रेस ने बंगाल में ममता बनार्जी के साथ तो आध्र में चन्द्रबाबू के साथ मिलकर चुनाव ना लडने का फैसला किया है । यानी काग्रेस इस हकीकत को बाखूबी समझ रही है कि लोकसभा चुनाव में जिसके पास ज्यादा सीट होगी उसकी दावेदारी ही चुनाव के बाद पीएम के उम्मीदवार के तौर पर होगी । और इसके लिये जरुरी है अपने बूते चुनाव लडना । तो ऐसे में प्रियंका की छवि कैसे नरेन्द्र मोदी के औरे को खत्म करेगी इसपर काग्रेस का ध्यान है । क्योकि 2014 में नरेन्द्र

मोदी जिस हंगामे और जिस तामझाम के साथ आये ये कोई कैसे भूल सकता है । और तब प्रचार में बीजेपी कही नहीं थी सिर्फ मोदी थे । लेकिन इसके उलट प्रियंका गांधी की इंट्री बेहद खामोशी से हुई । काग्रेस मुख्यालय में नेम प्लेट टांगने से लेकर कार्यकत्ताओ से बिना हंगामे मिलने के तौर तरीके ने ये तो साफ जतला दिया कि प्रिंयका को किसी प्रचार की जरुरत नहीं है । और काग्रेस का मतलब ही नेहरु गांधी परिवार है । लेकिन बीजेपी यहा भी अपने ही कटघरे में फंस गई । जब उसने खामोश प्रियका को खानदान और बिना हंगामे के राजनीति तले सिर्फ परिवार के अक्स में देखना शुरु किया । यानी प्रिंयका की छवि बीजेपी ने ही अपनी आलोचना से इतनी रहस्मयी और जादुई बना दिया कि प्रियका के बारे में जानने के लिये वोटरो में भी उत्सुकता जाग गई । और काग्रेस ने प्रियंका की छवि को मुद्दो को आसरे जिस तरह उभारने की कोशिश शुरु की है वह ना सिर्फ प्रियाका को दिरा गांधी से जोड रही है बल्कि इंदिरा के दौर में जिस तरह गरीबी हटाओ का नारा बुलंद हुआ । और जिसतरह मोदी के कारपोरेट प्रेम तले किसान मजदूर का सवाल काग्रेस उटा रही है उसमें चाहे अनचाहे 2019 का चुनाव अमीर बनाम गरीब की तरफ बढता जा रहा है । तो सवाल तीन है । पहला, क्या प्रियका को सिर्फ यूपी तक सीमित रखा जायेगा । दूसरा , क्या प्रिंयका को यूपी के सीएम के तौर पर प्रजोक्ट भी किया जायेगा । –तीसरा , क्या प्रिंयका की छवि राहुल के लिये मुश्किल पैदा करेगा । पर इन सवालो का जवाब भी काग्रेस के पास है । ध्यान से परखे तो प्रिंयका गांधी को चुनावी मैदान में तब उतारा गया जब राहुल गांधी की छवि पप्पू से इतर एक परिपक्व नेता के तौर पर बनने लगी । फिर राहुल गांधी ने अपनी राजनीति से मोदी को कारपोरेट के साथ खडा करने में राजनीतिक सफलता पायी । और –तीसरा , किसान और बेरजगारी के सवाल को जिस तरह राहुल ने मथा उसका ठीकरा मोदी सत्ता पर फूटा । और इसी अक्स में प्रियका का राजनीतिक इन्ट्री ही राहुल गांधी ने इस स्ट्रेटजी के साथ किया कि इंदरा की छवि में गरीबो के सावल को साथ लेकर अगर प्रयका प्रचार मैदान में कूदेगी तो मोदी का औरा खत्म होगा

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है

गणतंत्र के सूरज पर धुंधलके क्यों ?

▸ ललित गर्ग

गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसी दिन 26 जनवरी, 1950 को हमारी संसद ने भारतीय संविधान को पास किया। इस दिन भारत ने खुद को संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। उनत्तर वर्षों के बावजूद आज भी हमारा गणतंत्र कितनी ही कंटीली झाड़ियों में फँसा हुआ प्रतीत होता है। आज समाज एवं राष्ट्र विघटन एवं अनगिनत समस्याओं की कगार पर है। जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा जैसे सवालों ने अपने जहरीले डैने पसार रखे हैं। हिंसक वारदातां, प्राकृतिक आपदाओं एवं चारित्रिक अवमूल्यन की त्रासद घटनाओं से देश का हर आदमी सहमा–सहमा–सा है। मर्यादाओं के प्रति आस्था लड़खड़ाने लगी है। संस्कृति और परम्परा मात्र आदर्श बनकर रह गये हैं। जीवन मूल्यों की सुरक्षा में कानून और न्याय कम. जोर पड़ने लगे हैं। राजनीति में घुस आये स्वार्थी तत्वों ने लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। इन जटिल से जटिलतर होते हालातों के दौर में हमारे राष्ट्रीय पर्वों एवं प्रतीकों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। ये हमें न केवल एकता के सूत्र में बांधते हैं, बल्कि सवालों–वादों के खतरों के प्रति सचेत भी करते हैं।

राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हमें सिर्फ इस बात का अहसास ही नहीं कराता है कि अमुक दिन हम संप्रभु राष्ट्र बने थे या अमुक दिन हमारा अपना बनाया संविधान लागू हुआ था, बल्कि यह हमारी उन सफलताओं की ओर इशारा करता है जो इतनी लंबी अवधि के दौरान जी–तोड़ प्रयासों के फलस्वरूप मिलीं। यह हमारी विफलताओं पर भी रोशनी डालता है कि हम नाकाम रहे तो आखिर क्यों! क्यों हम राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को सुदृढ़ता नहीं दे पाये है? क्यों गणतंत्र के सूरज को राजनीतिक अपराधों, घोटालों और भ्रष्टाचार के बादलों ने घेर रखा है? हमने जिस संपूर्ण संविधान को स्वीकार किया है, उसमें कहा है कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह सही है और इसके लिए सर्वप्रथम जिस इच्छा–शक्ति की आवश्यकता है, वह हमारी शासन–व्यवस्था में सर्वात्मना नजर आनी चाहिए और ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारणों की खोज और उन्हें दूर करने के प्रयत्न इस गणतंत्र दिवस पर चर्चा का मुख्य मुद्दा होना चाहिए।

125 करोड़ के राष्ट्र को राजपथ पर निकलने वाली झांकियां एवं उनके बीच फहरा रहा तिरंगा ध्वज कह रहा है कि मुझे आकाश जितनी ऊंचाई दो, भाईचारे का वातावरण दो, मेरे सफेद रंग पर किसी निर्दोष के खून के छींटे न लगें, आंचल बन लहराता रहे। मुझे

हमारी सबसे बड़ी असफलता है कि आजादी के 70 वर्षों के बाद भी हम राष्ट्रीय चरित्र नहीं बना पाये। राष्ट्रीय चरित्र का दिन-प्रतिदिन नैतिक ह्रास हो रहा था।
हर गलत-सही तरीके से हम सब कुछ पा लेना चाहते थे। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्त्तव्य को गौण कर दिया था। इस तरह से जन्मे हर स्तर पर भ्रष्टाचार ने राष्ट्रीय जीवन में एक विकृति पैदा कर दी थी। देश में एक ओर गरीबी, बेरोजगारी और दुष्कार की समस्या है। दूसरी ओर अमीरी, विलासिता और अपव्यय है।

फहराता देखना है तो सुजलाम् सुफलाम् को सार्थक करना होगा। मुझे वे ही हाथ फहरायें जो गरीब के आंसू पोंछ सकें, मेरी धरती के टुकड़े न होने दें, जो भाई–भाई के गले में हो, गर्दन पर नहीं। अब कोई किसी की जाति नहीं पूछे, कोई किसी का धर्म नहीं पूछे। मूर्ति की तरह मेरे राष्ट्र का जीवन सभी ओर से सुन्दर हो। लेकिन बिन राजनीति चरित्र के सबकुछ धुंधला रहा है, सून हो रहा है।

हमें गणतंत्र दिवस को मनाते हुए एक ऐसे भारत को निर्मित करना है जो न केवल भौतिक दृष्टि से ही बल्कि नैतिक दृष्टि से भी सशक्त हो। गणतंत्र दिवस मनाते हुए पहली बार ऐसा आधुनिक भारत खड़ा करने की बात हो रही है जिसमें नये शहर बनाने, नई सड़कें बनाने, नये कल–कारखानें खोलने, नई तकनीक लाने, नई शासन–व्यवस्था बनाने के साथ–साथ नया इंसान गढ़ने की चर्चा है। एक शुभ एवं श्रेयस्कर भारत निर्मित हो रहा है। जबकि हर बार इस जश्न को मनाते हुए अनेक प्रश्न खडे रहे हैं, ये प्रश्न इसलिये खड़े हुए हैं क्योंकि आज भी आम आदमी न सुखी बना, न समृद्ध। न सुरक्षित बना, न संरक्षित। न शिक्षित बना और न स्वावलम्बी। अर्जन के सारे स्रोत सीमित हाथों में सिमट कर रह गए। समृद्धि कुछ हाथों में सिमट गयी है। स्वार्थ की भूख परमार्थ की भावना को ही लील गई। हिंसा, आतंकवाद, जातिवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रीयवाद तथा धर्म, भाषा और दलीय स्वार्थों के राजनीतिक विवादों ने आम नागरिक का जीना दुर्भर कर दिया।बुद्ध, महावीर, गांधी हमारे आदर्शों की पराकाष्ठा हैं। पर विडम्बना देखिए कि हम उनके जैसा आचरण

नहीं कर सकते– उनकी पूजा कर सकते हैं। उनके मार्ग को नहीं अपना सकते, उस पर भाषण दे सकते हैं। आज के तीव्रता से बदलते समय में, लगता है हम उन्हें तीव्रता से भुला रहे हैं, जबकि और तीव्रता से उन्हें सामने रखकर हमें अपनी व राष्ट्रीय जीवन प्रणाली की रचना करनी चाहिए। गांधी, शास्त्री, नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लोहिया के बाद राष्ट्रीय नेताओं के कद छोटे होते गये और परछाइयां बड़ी होती गईं। हमारी प्रणाली में तंत्र ज्यादा और लोक कम रह गया है। यह प्रणाली उतनी ही अच्छी हो सकती है, जितने कुशल चलाने वाले होते हैं। लेकिन कुशलता तो तथाकथित स्वार्थों की भेंट चढ़ गयी। लोकतंत्र श्रेष्ठ प्रणाली है। पर उसके संचालन में शुद्धता हो। लोक जीवन में ही नहीं लोक से द्वारा लोक हित के लिये चुने प्रतिनिधियों में लोकतंत्र प्रतिष्ठापित हो और लोकतंत्र में लोक मत को अधिमान मिले– यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी अपेक्षा है। हमारी सबसे बड़ी असफलता है कि आजादी के 70 वर्षों के बाद भी हम राष्ट्रीय चरित्र नहीं बना पाये। राष्ट्रीय चरित्र का दिन–प्रतिदिन नैतिक ह्रास हो रहा था।

हर गलत–सही तरीके से हम सब कुछ पा लेना चाहते थे। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्त्तव्य को गौण कर दिया था। इस तरह से जन्मे हर स्तर पर भ्रष्टाचार ने राष्ट्रीय जीवन में एक विकृति पैदा कर दी थी। देश में एक ओर गरीबी, बेरोजगारी और दुष्कार की समस्या है। दूसरी ओर अमीरी, विलासिता और अपव्यय है। देशवासी बहुत बड़ी विसंगति में जी रहे हैं। एक ही देश की धरती पर जीने वाले कुछ लोग पैसे को पानी की तरह बहाएँ और कुछ लोग भूखे पेट सोएं–इस असंतुलन की समस्या को नजरंदाज न कर इसका संयममूलक हल खोजना चाहिए। भारत के समक्ष चुनौतियां गंभीर है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी और सार्वजनिक सेवाओं के मोर्चे पर सरकारें एकदम नाकाम रही हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र इतना महंगा कर दिया गया है कि अब आम भारतीय परिवार बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्त में भारत के गरीब तबके की तस्वीर कैसी होगी। यह सोच कर खुश हुआ जा सकता है कि हम दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, फ्रांस को पछाड़ चुके हैं और ब्रिटेन को पीछे छोड़ने वाले हैं, लेकिन इसके स्याह पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समावेशी विकास हो या फिर मानव पूंजी सूचकांक, भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों से भी पीछे है।

दरअसल भारत अब अमीरों की मुट्ठी में है। नीतियां अमीरों के लिए ही बन रही हैं और इनका असर भी साफ नजर आ रहा है। कर्ज लेकर मौज करने वालों की संख्या में इजाफा भी अमीरों की संख्या को बढ़ाता है। ऐसे में गरीबों की तादाद तो बढ़ेगी ही, लेकिन उनकी संपत्ति और ताकत घटेगी। बढ़ती असमानता से उपजी चिंताओं के बीच देश में करोड़पतियों की तादाद का तेजी से बढ़ना खुश होने का नहीं, बल्कि गंभीर चिन्ता का विषय है। गरीबी अमीरी की बढ़ती खाई को पाटकर ही हम देश की अस्मिता एवं अखण्डता को बचा सकते हैं। सरकार संचालन में जो खुलापन व सहजता होनी चाहिए, वह गायब है। सहजता भी सहजता से नहीं आती। पारदर्शिता का दावा करने वाले सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही चालबाजियों का पर्दा डाल लेते हैं। पर एक बात सदैव सत्य बनी हुई है कि कोई पाप, कोई जुर्म व कोई गलती छुपती नहीं। वह रूस जैसे लोहे के पर्दे को काटकर भी बाहर निकल आती है। वह चीन की दीवार को भी फाँद लेती है। हमारे साउथ ब्लाकों एवं नॉर्थ ब्लाकों में तो बहुत दरवाजे और खिड़कियाँ हैं। कुछ चीजों का नष्ट होना जरूरी था, अनेक चीजों को नष्ट होने से बचाने के लिए। जो नष्ट हो चुका वह कुछ कम नहीं, मगर जो नष्ट होने से बच गया वह उस बहुत से बहुत है। यह भी सच है कि इन 69 सालों में जहां हमने बहुत कुछ हासिल किया, वहीं हमारे संकल्पों में बहुत कुछ आज भी आधे–अधूरे सपनों की तरह हैं। भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सांप्रदायिक वैमनस्य, कानून–व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे तमाम क्षेत्र हैं जिनमे हम आज भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हालांकि इन्हें लेकर हमारे कदम लगातार सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि एक राष्ट्र के रूप में हम इन संकल्पों को लगातार याद रखें और दोहराएं, तभी गणतंत्र दिवस मनाने की सार्थकता है।

तू इधर-उधर की बात न कर...

देश में तथाकथित राष्ट्रवाद के नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस समय राजनैतिक विमर्श का स्तर इस कद्र गिर गया है कि राजनैतिक दल एक-दूसरे को अपना राजनैतिक विरोधी नहीं बल्कि दुश्मन समझने लगे हैं। जन सरोकारों से जुड़े सबसे मुख्य मुद्दों का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। आज अमेरिकी डॉलर की कीमत 72 रुपये के लगभग होने को है। परंतु अब इन्हें देश की इज्जत गिरती दिखाई नहीं देती?

▸ तनवीर जाफरी

लोकसभा चुनावों के बादल सिर पर मंडराने लगे हैं। मौकापरस्ती तथा गठबंधनों में जोड़–तोड़ की कवायद शुरू हो चुकी है। नित नए राजनैतिक गठबंधन बनने व बिगडने की खबरें आने लगी हैं। दुर्भाग्यवश देश की जनता देख रही है कि चुनावी मुद्दों का पूरा का पूरा फोकस जन सरोकारों तथा विकास से हटकर मंदिर–मस्जिद,धर्म–जाति,भय–भावनाओं तथा बेचारगी पर केंद्रित हो चुका है। सबका साथ–सबका विकास का नारा देकर अबकी बार मोदी सरकार के जिस लक्ष्य को भाजपा ने 2014 में पूरी सफलता के साथ हासिल किया था वही भाजपा अब अपने 2014 के किए गए वादों को पूरा न कर पाने की स्थिति में जनता के मध्य दूसरे निरर्थक तथा जन सरोकारों से कोई वास्ता न रखने वाले मुद्दों को उछाल कर पुनरू सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है।

हद तो यह है कि राजनैतिक विमर्श का स्तर इतना गिर चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोकि स्वयं को देश का सेवक व चौ. कीदार बताते रहते हैं उन्हें साफतौर पर संसद से लेकर सड़कों तक विपक्षी नेताओं द्वारा–चौकीदार चोर है कहकर संबोधित किया जाने लगा है। उधर प्रधानमंत्री अपने विरोधियों को चोरों की जमात व लूटेरों का गठबंधन आदि विशेषणों से नवाज रहे हैं। मतदाताओं को ऐसे–ऐसे अनावश्यक इतिहास सुनाए जा रहे हैं ताकि उनके दिलों में विपक्ष या विपक्षी दलों के गठबंधन के प्रति भय पैदा हो और विपक्ष, देश का दुश्मन,राष्ट्रविरोधी तथा हिंदू विरोधी नजर आने लगे।

कोलकाता में पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बैनर्जी द्वारा एक विपक्षी महागठबंधन बनाने का प्रयास किया गया। इसमें देश के अधिकांश विपक्षी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परंतु लोगों का ध्यान सबसे अधिक भाजपा से ही संबंध रखने वाले नेताओं यशवंत सिन्हा,अरूण शैरी व शत्रुघन सिन्हा के भाषणों पर गया। इन्हीं नेताओं ने प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा किया तथा सार्वजनिक तौर पर चौ. कीदार चोर है का उद्घोष किया गया। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के मध्य एक अप्रत्याशित चुनावी गठबंधन हुआ। इस गठबंधन का सफल प्रयोग गोरखपुर तथा फूलपुर की लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में साफतौर पर उस समय देखा गया था जबकि उत्तर प्रदेश के मु यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उपमु यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या दोनों ही अपनी–अपनी लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद हार गए थे। सपा–बसपा गठबंधन इन सीटों पर विजयी हुआ था। अब चूंकि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व एक बार फिर इन्हीं दोनों दलों का गठबंधन हो गया है लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटना स्वाभाविक है। यही उत्तर प्रदेश था जिसने 2014 में भाजपा को प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर विजय

दिलाई थी और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बदौलत ही केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार का गठन संभव हो सका। अब चूंकि सपा–बसपा के साथ आने के बाद भाजपा के उत्तर प्रदेश से 73 सीटें जीतने वाले सपने धराशायी हो सकते है लिहाजा भाजपा के चाणक्य समझे जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 के चुनावों की तुलना पानीपत के युद्ध से कर डाली। शाह ने देश के मतदाताओं में भय पैदा करते हुए कहा कि–2019 का युद्ध सदियों तक असर डालने वाला है इसलिए यह युद्ध जीतना जरूरी है। उन्होंने अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण कराए जाने की बात भी कही।

इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाए विपक्षी गठबंधन पर आक्रामक हमले बोले जा रहे हैं। देश के बुद्धिजीवी तथा मीडिया जगत के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री से बार–बार यह पूछा जा रहा है कि आपने अपने पूरे शासनकाल में एक बारभी पत्रकारों को संबोधित क्यों नहीं किया? मुख्य धारा के मीडिया से सवाल–जवाब करने से आखिर आप क्यों कतरा रहे हैं। परंतु प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से तथा प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली मन की बात में भी आज तक इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया गया कि आखिर प्रधानमंत्री मीडिया से रूबरू क्यों नहीं होते? देश में नौकरियों का अकाल पडने के बावजूद सामान्य वर्ग के लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण का झुनझुना थमाकर स्वर्णों को लुभाने की कोशिश हो रही है तो कभी तीन तलाक जैसे गैरजरूरी विषय को अपने राजनैतिक लाभ के लिए उछाला गया है। कभी प्रधानमंत्री यह फरमा रहे हैं कि मैंने जिनकी कमाई रोकी वे मुझसे बदला लेने के लिए एक हो रहे हैं। कभी फरमाते हैं कि मैंने सरकारी धन की लूट रोकी है इसलिए मुझे हटाने की साजिश विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है तो कभी कम्युनिस्टों पर यह कहकर हमलावर हो रहे हैं कि वे भारतीय संस्कृति का स मान नहीं करते। देश में तथाकथित राष्ट्रवाद के नए–नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस समय राजनैतिक विमर्श का स्तर इस कद्र गिर गया है कि राजनैतिक दल एक–दूसरे को अपना राजनैतिक विरोधी नहीं बल्कि दुश्मन समझने लगे हैं। जन सरोकारों से जुड़े सबसे मुख्य मुद्दों का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। आज अमेरिकी डॉलर की कीमत 72 रुपये के लगभग होने को है। परंतु अब इन्हें देश की इज्जत गिरती दिखाई नहीं देती? पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों ने मंहगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। किसानों द्वारा रिकॉर्ड तौर पर पिछले पांच वर्षों में धरने–प्रदर्शन तथा आत्महत्याएं की गई हैं। इनकी समस्याओं को दूर करने के बजाए पानीपत की लड़ाई का इतिहास याद दिलाया जा रहा है? रोजगार न देने के बावजूद भाजपाई युवाओं से अपने लिए वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनके अनुसार भाजपा के अति. रिक्त शेष सभी विपक्षी दल वामपंथी सोच से प्रेरित हैं और वामपंथी भारतीय संस्कृति का स मान नहीं करते। गोया भारतीय संस्कृति की रक्षा करना तथा इसके स्वामित्व का अधिकार केवल इन्हीं भाजपाईयों को है जिन्होंने भारतवर्ष के स्वाधीनता संग्राम में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई? भारतवर्ष में जन्मे यहां की मिट्टी में पले तथा अलग–अलग राजनैतिक विचारधाराओं के मानने वाले लोगों को राष्ट्रविरोधी बताना या भारत का दुश्मन कह देना राष्ट्रवाद की इनकी अपनी परिभाषा में शामिल है।

देश में जन सरोकारों से जुड़े जो सबसे जरूरी मुद्दे हैं उनमें अमीरों व गरीबों के बीच की खाई को पाटना, युवाओं को रोजगार मुहैया कराना,देश में सभी लोगों के लिए शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराना,देश में धर्म व जाति के मतभेदों को समाप्त कर परस्पर सद्भाव व शांति का वातावरण तैयार करना, देश के सभी लोगों को समान रूप से स्वास्थय सुविधा मुहैया कराना,जमाखोरी,चोरबाजारी व मंहगाई रोकना, समाज को नफरत व भय के नाम पर बंटने से रोकना आदि सर्वप्रमुख हैं। देश का विकास वास्तव में इन्हीं समस्याओं का समाधान करने पर ही निर्भर है। परंतु आज इन जन सरोकारों की तो कोई बात ही नहीं करता। एक–दूसरे को नीचा दिखाने तथा जनता को भयभीत करने की घिनौनी सियासत की जा रही है। आज के सत्ताधारियों का विरोध तो दूर इनकी आलोचना करना भी राष्ट्रविरोध जैसा हो गया है। न इन्हें नोटबंदी का हिसाब व जवाब देने में कोई दिल. चस्पी है न ही राफेल विमान सौदे से संबंधित लोकसभा में पूछे जा रहे प्रश्नों का इनके पास कोई जवाब है। उल्टे कभी यही सत्ताधारी हत्यारों के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं तो कभी बलात्क. ारियों के समर्थन में जुलूस निकालते नजर आ रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश में बेतहाशा फर्जी पुलिस मुठभेड़ों की +खबरें आ रही हैं तो कभी इनके सांसद व मंत्री हत्यारों को स मानित करते दिखाई दे जाते हैं। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनावों में देश की जनता अपने रहबरों से पूछने जा रही है कि–तू इधर–उधर की बात न कर– ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं,तेरी रहबरी का सवाल है।

बाजारवाद के इस दौर में प्रेम भी तोहफों का मोहताज हो गया

▸ डॉ. नीलम महेंद्र

वैलेंटाइन डे, एक ऐसा दिन जिसके बारे में कुछ सालों पहले तक हमारे देश में बहुत ही कम लोग जानते थे, आज उस दिन का इंतजार करने वाला एक अच्छा खासा वर्ग उपलब्ध है। अगर आप सोच रहे हैं कि केवल इसे चाहने वाला युवा वर्ग ही इस दिन का इंतजार विशेष रूप से करता है तो आप गलत हैं। क्योंकि इसका विरोध करने वाले बजरंग दल, हिन्दू महासभा जैसे हिन्दूवादी संगठन भी इस दिन का इंतजार उतनी ही बेसब्री से करते हैं। इसके अलावा आज के भौतिकवादी युग में जब हर मौके और हर भावना का बाजारीकरण हो गया हो, ऐसे दौर में गिफ्ट्स, टेडी बियर, चॉकलेट और फूलों का बाजार भी इस दिन का इंतजार उतनी ही व्याकुलता से करता है

आज प्रेम आपके दिल और उसकी भावनाओं तक सीमित रहने वाला केवल आपका एक निजी मामला नहीं रह गया है। उपभोक्तावाद और बाजारवाद के इस दौर में प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति दोनों ही बाजारवाद का शिकार हो गए हैं। आज प्रेम छुप कर करने वाली चीज नहीं है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर करने वाली चीज है। आज प्यार वो नहीं है जो निस्वार्थ होता है और बदले में कुछ नहीं चाहता बल्कि आज प्यार वो है जो त्याग नहीं अधिकार मांगता है।

भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश को प्यार जताने के लिए विदेश से किसी दिन को आयात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह तो त्योहारों का वो देश है जो मानवीय संबंधों ही नहीं बल्कि प्रकृति के साथ भी अपने प्रेम और कृतज्ञता को अनेक त्योहारों के माध्यम से प्रकट करता है। जैसे गुरु पूर्णिमा (गुरु शिष्य), रक्षा बंधन, भाई दूज (भाई बहन), करवाचौथ (पति पत्नी), गौरी गणेश व्रत (माता और संतान), मकर संक्रांति (पिता पुत्र प्रेम), पितृ पक्ष (पूर्वजों), वसंत पंचमी (प्रेमी युगल), गंगा दशहरा, तुलसी विवाह (प्रकृति), हमारे देश में इस प्रकार के अनेक पर्व विभिन्न रिश्तों में प्रेम प्रकट करने का एक

क्योंकि आज मल्टीनेशनल कंपनियाँ बड़ी चालाकी से हमें यह समझाने में सफल हो गई हैं कि प्रेम को तो महँगे उपहार देकर जताया जाता है। वे हमें करोड़ों के विज्ञापनों से यह बात समझा कर अरबों कमाने में कामयाब हो गई हैं कि इफ यू लव समवन शो इट, यानी, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो जताइए और वैलेंटाइन डे इसके लिए सबसे अच्छा दिन है। यह वाकई में खेद का विषय है कि राधा और मीरा के देश में जहाँ प्रेम की परिभाषा एक अलौकिक एहसास के साथ शुरू होकर समर्पण और भक्ति पर खत्म होती थी आज उस देश में प्रेम की अभिव्यक्ति तोहफों और बाजारवाद की मोहताज हो कर रह गई है।

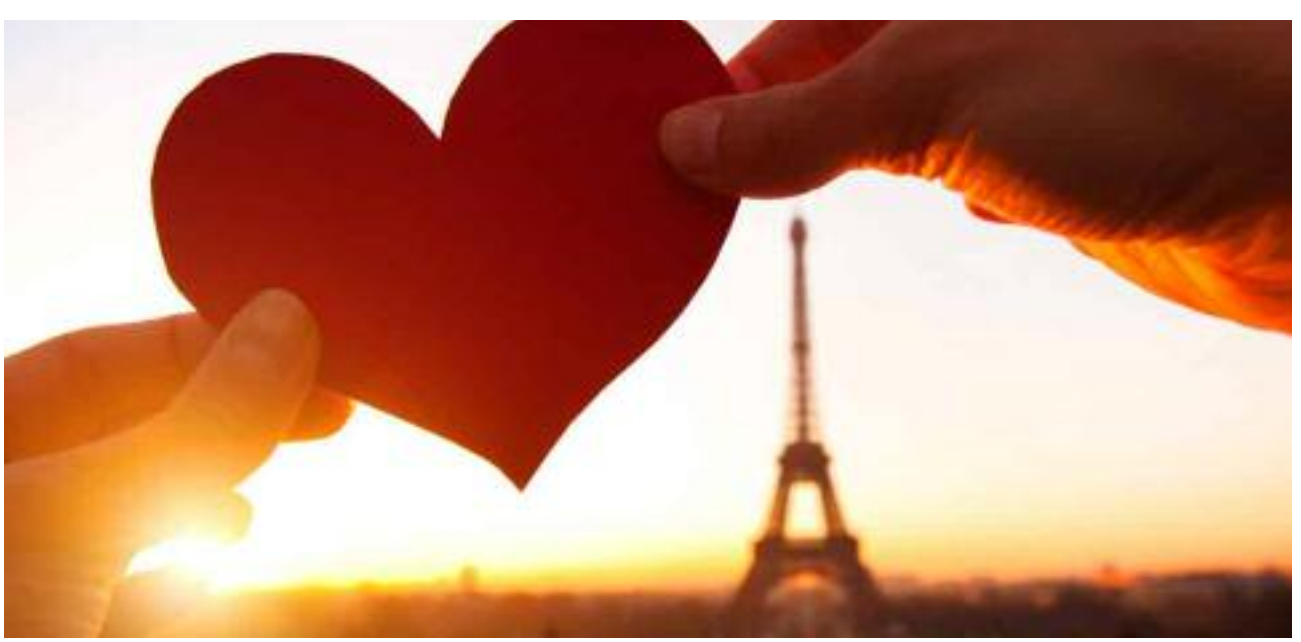

उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक समाज के रूप में पश्चिमी अंधानुकरण के चलते हम विषय की गहराई में उतर कर चीजों को समझकर उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसकी उपयो. गिता नहीं देखते। सामाजिक परिपक्वता दिखाने की बजाए कथित आधुनिकता के नाम पर बाजारवाद का शिकार हो कर अपनी मानसिक गुलामी ही प्रदर्शित करते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि वैलेंटाइन डे आखिर क्यों मनाया जाता है।

ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व 278 में रोमन साम्राज्य में सम्राट मौरस औरेलियस क्लौडीयस गॉथियस को अपनी सेना के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। उन्हें ऐसे नौजवान या फिर ऐसे युवा ढूंढ़ने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जो सेना में भर्ती होना चाहें। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अपनी पत्नियों और परिवार के प्रति मोह के चलते लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। तो उन्होंने अपने शासन में शादियों पर ही पाबंदी लगा दी। तब संत वैलेंटाइन ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और वे चोरी छुपे प्रेमी युगलों का विवाह करा देते थे। जब सम्राट क्लौडीयस को इस बात का पता चला तो उन्होंने संत वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर उनको मृत्यु दंड दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी याद में ही वैलेंटाइन डे मनाया जाता है।

तो अब प्रश्न यह है कि हमारे देश में जहाँ की संस्कृति में विवाह हमारे जीवन का एक एहम संस्कार है उस देश में ऐसे दिन को त्यौहार के रूप में मनाने का क्या औचित्य है जिसके मूल में विवाह नामक संस्था का ही विरोध हो ? क्योंकि भारत में विवाह का कभी भी विरोध नहीं किया गया बल्कि यह तो खुद ही पांच–छह दिनों तक चलने वाला दो परिवारों का सामाजिक उत्सव है। दरअसल यहां यह समझना भी जरूरी है कि मुख्य विषय वैलेंटाइन डे के विरोध या समर्थन का नहीं है बल्कि किसी दिन या त्यौहार को मनाने के महत्व का है।

किसी भी त्यौहार को मनाने या किसी संस्कृति को अपनाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन हमें किसी भी कार्य को करने से पहले इतना तो विचार कर ही लेना चाहिए कि इसका औचित्य क्या है ? कहा जाता है कि वैलेंटाइन डे प्यार जताने का दिन है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि इस दिन आप अपने प्रेमी को ही अपना प्यार जताएं, आप अपने माता पिता को, गुरु को किसी को भी अपना प्यार जता सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक तथ्य। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश को प्यार जताने के लिए विदेश से किसी दिन को आयात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह तो त्योहारों का वो देश है जो मानवीय संबंधों ही नहीं बल्कि प्रकृति के साथ भी अपने प्रेम और कृतज्ञता को अनेक त्योहारों के माध्यम से प्रकट करता है। जैसे गुरु पूर्णिमा (गुरु शिष्य), रक्षा बंधन, भाई दूज (भाई बहन), करवाचौथ (पति पत्नी), गौरी गणेश व्रत (माता और संतान), मकर संक्रांति (पिता पुत्र प्रेम), पितृ पक्ष (पूर्वजों), वसंत पंचमी (प्रेमी युगल), गंगा दशहरा, तुलसी विवाह (प्रकृति), हमारे देश में इस प्रकार के अनेक पर्व विभिन्न रिश्तों में प्रेम प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम हैं।

इसके बावजूद अगर आज भारत जैसे देश में वसंतोत्सव की जगह वैलेंटाइन डे ने ले ली है तो कारण तो एक समाज के रूप में हमें ही खोजने होंगे। यह तो हमें ही समझना होगा कि हम केवल वसंतोत्सव से नहीं प्रकृति से भी दूर हो गए। केवल प्रकृति ही नहीं अपनी संस्कृति से भी दूर हो गए। हमने केवल वैलेंटाइन डे नहीं अपनाया बाजारवाद और उपभोगतावाद भी अपना लिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हम मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों की कठपुतली बन कर खुद अपनी संस्कृति के विनाशक बन जाते हैं जब हम अपने देश के त्योहारों को छोड़कर प्यार जताने के लिए वैलेंटाइन डे जैसे दिन को मनाते हैं।

किसका झंडा होगा बुलंद ?

भाजपा, रालोद, सपा, बसपा और कांग्रेस में खेमेबंदी शुरू

देशभर में अपनी बुलंदियों के लिए प्रसिद्द दिल्ली से कुछ ही घंटे की दूरी पर स्थित बुलंदशहर यूँ तो अपनी अलग पहचान रखता है लेकिन सियासी रूप से भी अपना अहम स्थान रखता है । पूर्व मुख्यमंत्री और अब राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का भी राजनैतिक क्षेत्र यह रहा है । कल्याण सिंह ने लोकसभा में बुलंदशहर का प्रतिनिधित्व भी किया है उनका प्रभाव अभी भी इस लोकसभा क्षेत्र में रहता हैं । 2014 की मोदी लहर में उन्होंने भोला सूर्यवंशी को टिकट दिलवाया और भोला बड़ी जीत के साथ लोकसभा पहुंचे । यह माना जाता है कि बाबू जी (कल्याण सिंह) का जिसको आशीर्वाद मिला वह यहाँ से सांसद हो गया । अब 2019 में महागठबंधन होने के बाद सारे मिथक टूटने के आसार हैं ।

सपा–बसपा और रालोद के गठबंधन के बाद बुलंदशहर पर टिकट पाने के लिए दावेदारों की संख्या बड गयी है । सूत्रों का कहना है कि बुलंदशहर पर बसपा चुनाव लड़ेगी । बसपा से टिकट के लिए मेरठ जिले के पूर्व विधायक योगेश वर्मा सबसे ऊपर हैं । बसपा से योगेन्द्र शिरीष,सुनीता चौहान के नाम भी चर्चाओं में हैं । सपा से भी कमलेश बाल्मीकि. महेंद्र बाल्मीकि, नरेन्द्र गौतम, रविन्द्र बाल्मीकि दावेदारी कर रहे हैं । वहीँ कांग्रेस से पूर्व अफसर देवीदयाल, पूर्व विधायक वंशी पहाड़िया के नाम चर्चाओं में हैं । जिले में जाट मतदाताओं की संख्या भी अच्छी होने के चलते राष्ट्रीय लोकदल में भी दावेदारी बड़ी है । रालोद के खाते से महागठबंधन में पूर्व प्रत्याशी अंजू मुस्कान, अतुल बाल्मीकि, नरेन्द्र सिंह ताल ठोक रहे हैं । केंद्र में सत्तारुण भाजपा में ज्यादा घमासान है । वर्तमान सांसद भोला सूर्यवंशी टिकट को बचाए रखने के लिए जोर लगाये हुए हैं तो वहीँ पूर्व विधायक होराम सिंह, पूर्व मंत्री अशोक प्रधान, छत्रपाल सूर्यवंशी, जैसे नाम टिकट के लिए खेमेबंदी कर रहे हैं । जिले में 2019 में मोदी लहर चलेगी या महागठबंधन की आंधी यह मतदाता तय करेंगे लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिले में भाजपा को सीट बचाना बड़ी चुनौती होगी ?

गुर्जरों और सपा के दिग्गज नेता दिनेश गुर्जर को जान का खतरा

पश्चिमी यूपी की राजनीति में वर्चस्व रखने वाले अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता दिनेश गुर्जर को इन दिनों जान का खतरा सता रहा है । पश्चिमी यूपी के एक बड़े माफिया और जेल में बंद एक कुख्यात से दिनेश गुर्जर को जान का खतरा है । सरकार द्वारा सुरक्षा कम किये जाने से गुर्जरों और सपा के इस बड़े नेता ने राजनैतिक और सामाजिक सक्रियता भी कम कर दी है । दिनेश गुर्जर की सक्रियता कम होने से सियासी हल्के में चर्चाओं का माहौल है । दरअसल दिनेश गुर्जर बुलंदशहर की राजनीति में अपना अहम रसूख रखते हैं । सरकार में वह सपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं और अब प्रदेश सचिव हैं। मुलायम सिंह और अखिलेश के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है । दिनेश अखिल भारतीय गुर्जर महासभा यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं । पश्चिमी यूपी के गुर्जर समुदाय के उनकी अच्छी पकड़ है । पश्चिमी यूपी के एक बड़े माफिया और कुख्यात बदमाश से उनका छत्तीस का आंकड़ा है । पिछले लंबे समय से उनपर सुरक्षा है । अखिलेश सरकार ने तो उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रखी थी जो योगी सरकार में भी रही । लेकिन पिछले कुछ माह से भाजपा के बड़े नेता के इशारे पर उनका सियासी रसूख कम करने के लिए सुरक्षा में कटौती की गई है ।सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों एक बड़े कुख्यात बदमाश के पैरोल पर आने से दिनेश गुर्जर की जान को खतरा को बड़ गया है । जिसके चलते दिनेश गुर्जर ने राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमो में जाना कम कर दिया है । पहले जहां वह देर शाम तक कार्यक्रमो में रहते थे लेकिन अब सिर्फ दिन में ही आना–जाना करते हैं । इतना ही नहीं दिनेश चुनिंदा करीबियों के ही कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं । दिनेश की सक्रियता कम होने बुलंदशहर सहित कई जिलों में सियासी चर्चाओं का दौर जारी है । अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर होता है ।

समझिए चंदे के सियासी अर्थशास्त्र को !

▶ ओमप्रकाश तिवारी

लोकतंत्र में यह लगभग यक्ष प्रश्न है कि लोग यानी जनता अपने विवेक से अपना जनप्रतिनिधि चुनती है! ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव के समय धनबल और बाहुबल से जनता को गुमराह और भ्रमित किया जाता है। प्रचार के माध्यम से इस इस तरह के दावे और वादों तथा झूठ का ऐसा भ्रमजाल सृजित किया जाता है कि अच्छे से अच्छे विवे. कवान, तर्कशील और चेतनशील भी फंस जाता है। दुविधा का संजाल ऐसा बनता है कि सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यह सब मुमकिन होता है पैसे,धन व पूंजी से।

राजनीतिक दलों को यह धन देता कौन है ?

धनपति, पूंजीपति यानी पैसे वाला चंदे के नाम पर देता है। जो जितना जिसे देता है सत्ता में आने पर उतना ही उससे वसूलता है। इसे कहते हैं राजनीति का अर्थशास्त्र। इसी अर्थशास्त्र से राजनीति चलती है और चलता है लोकतंत्र।

इसे और सरल तरीके से समझना है तो कारपोरेट को सत्ता की तरफ से मिलने वाली मदद से समझ सकते हैं। वर्तमान की केंद्र सरकार ने कुछ पूंजीपतियों सहित कारपोरेट को काफी मदद की है जिसपर पर चर्चा नहीं होती। इस पर चर्चा करने वाले को देशद्रोही बता दिया जाता है या झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। इसके विपरीत किसान, मजदूर और गरीबों के लिए कोई नीति बनती है या सरकार मदद देती है तो हाय तौबा मच जाती है। जबकि वोट यही लोग देते हैं। सरकार यही लोग चुनते हैं। मतदान केंद्र तक यही लोग जाते हैं। अपना जनप्रति. निधि यही चुनते हैं। जो चुने जाने के बाद इनके लिए काम नहीं करते और इनसे मिलते भी नहीं हैं। कोई फैसला लेने से पहले इनसे पूछते तक नहीं है। दल छोड़ देते हैं और पाला बदल लेते हैं बिना यह सोचे कि जिसने उन्हें चुना है उसकी राय क्या है और वह क्या सोचता है ?

वह ऐसा क्यों करते हैं ?

क्योंकि वह जनसेवक नही हैं, वह पैसे वाले हैं। पैसा कमाने के लिए जनसेवक का रूप धर कर राजनीति में आते हैं और 5 साल में ही मालामाल हो जाते हैं। किसी जनप्रतिनिधि के पास पांच साल में जो अकूत संपत्ति आती है वह कहां से आती है, इसे पूछने वाला कोई नहीं होता है। यह भी लोकतंत्र में सियासत का अर्थशास्त्र है।

एक प्रमुख गैर सरकारी विचार मंच एसोशिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने 16 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि सत्ताधारी दल भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को मिले चंदे का ज्यादा हिस्सा प्रूडेंट इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है। इस संगठन के पीछे देश के कई बड़े कारपोरेट घराने हैं। जिनमें रियल एस्टेट और टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में सभी दलों को 469.89 करोड़ रुपये चंदे में मिले हैं। इनमें से केवल भाजपा को 437.04 करोड़ रुपये मिले हैं। जबकि कांग्रेस को केवल 26.65 करोड़ रुपये मिले हैं। कारपोरेट घरानों ने भाजपा को चंदे के रूप में 400.23 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं कांग्रेस को भी 19.29 करोड़ रुपये कारपोरेट घरानों से मिले हैं। रिपोर्ट बताती है कि 90 फीसदी चंदा कारपोरेट घरानों ने जबकि 10 फीसदी निजी तौर पर दिया गया है। 208.56 करोड़ रुपये अकेले दिल्ली से आये जो कुल चंदे का करीब 50 फीसदी है।

इस चंदे का राजनीतिक दल क्या करते हैं ?

इसका जवाब वैसे तो ऊपर दिया जा चुका है लेकिन एक उदाहरण मात्र से भी समझ सकते हैं। निर्वाचन आयोग को दिये गये खर्च के विवरण में भाजपा ने बताया है कि उसने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार पर 122.68 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव प्रचार पर 14 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। यह प्रचार क्या होता है ऊपर बताया गया है। प्रचार से ही जनता के विवेक का हरण किया जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वह उतना बड़ा प्रचारक। प्रचार से जनता को भ्रमित करो, झूठे तथ्यों से गुमराह करो, थोथे वादों से दुविधा में डालो और जीत हासिल करो। उसके बाद उसकी सेवा करो जिसने चंदा दिया है। जिसने चुना है वह जाय भाड़ में। इसे इस तरह से भी समझें कि राफेल सौदा चन्दा देने वालों की पक्षकारी है तो किसानों की कर्ज माफी जनता की। लेकिन लोकतंत्र में यह केवल प्रतीक है। जिसे जनता को समझना होता है। सियासत में प्रतीक अहम हो गए हैं इसलिए उसे समझना भी जरूरी हो गया है।

ACN GROUP OF INSTITUTIONS

ACN GROUP Since 1995

23 Years

A Challenge for Most Rewarding Career

(Approved By A.I.C.T.E New Delhi & Affiliated to U.P.T.U. & B.T.E., Luckhnow)

ACN INTERNATIONAL SCHOOL

Developing Global Leaders

Facilities : Day Boarding School | Hostel for Girls & Boys | Transport Facilities | Horse Riding | Gymnasium & Summer Camp

ADMISSION OPEN

Nursery to Class X

Call: 9634296781

BTCमें सीधे प्रवेश

BTC in Minority Quota

Qualification : Graduate (50%)

अलीगढ़ का प्रथम अल्पसंख्यक बी. टी. सी. संस्थान

8439750205, 9412735085

B. Tech.

College Code - 339

Civil, ME, EC, EE, Cs, IT, AG

MD

UNANI(2017-18)

- Moalijat (Medicine)- (4)
- Kulliyat (Physiology) - (9)
- Tahaffuz wa Samaji Tib - (Social & Preventive Medicine/Hy

BAMS | BUMS

Call: 9412735085

MBA

HRM, MM, FM, IBM, IT

DEGREE :

B.Sc. Nursing (4 Years Course)

Post Basic B.Sc. Nursing (2 Years Course)

PGDM

HRM, MM, FM, IBM,

DIPLOMA :

GNM (3 Years Course)

ANM (2 Years Course)

Call 9897763288

DIPLOMA POLYTECHNIC

B. T. E. Code - 608

Civil, ME, EE, EC, Architec

DIPLOMA IN PHARMACY (AYURVEDIC)

Qualification : 12th (Science) Duration - 3 Years

DIPLOMA IN NURSING (AYURVEDIC)

Qualification : 12th Duration - 3 Years

B. Ed.

2 Years Course — PHYSIOTHERAPY

2 Years Course — OPTOMETRY

BBA

BCA

Homeopathic Pharmacy

(उत्तर प्रदेश होम्योपैथी बोर्ड, लखनऊ से मान्यता प्राप्त)

(2 Year Course)[12 with Maths + Bio (Any)]

सरकारी होम्योपैथी कॉलेज में नौकरी हेतु पद खाली

Head Office: Grand Plaza, Marris Road, Civil Lines, Aligarh Tel. 0571-3259119, Mob. 7055434208

Campus: ACN City, Qasimpur Power House Road, Aligarh Mob.: 09456618910, 09927882068, 09927319169

Visit us Online - www.acngi.edu.in, Engineering College-www.acncems.edu.in

ITM GROUP OF INSTITUTIONS

ITM GROUP OF INSTITUTIONS ALIGARH

OM TRUST

ADMISSION OPEN 2019-20

B.Ed. Couselling Code - AS 1120

COURSES OFFERED

B.TECH • CIVIL • ME • EEE • CSE • IT • EC

M.TECH • ECE • CSE • ME

MBA • Fin. • HR • Mkt. • IB • IT

DIPLOMA • CIVIL • EEE • ME(Production) • ME(Automobile)

B.Ed | **D.El.Ed.(BTC)** | **D.Pharma** | **ITI**

- CAMPUS PLANNED FOR 10000 STUDENTS
- STUDENT SUPPORT SERVICES
- EXCELLENT ACADEMIC INFRASTRUCTURE
- WORLD-CLASS ELECTRONIC LIBRARY
- EXCELLENT SPORTING INFRASTRUCTURE
- SEPARATE HOSTELS FOR BOYS AND GIRLS
- WI-FI CAMPUS

Khair Road, Karsua, Aligarh - 202440, (U.P.), INDIA, Phone : 0571-2213721,
Email : itmaligarh@gmail.com Website : www.itmaligarh.com

ADMISSION HELPLINE: 09927033475, 09927635500